● वर्ष-5

● अंक-236

रायपुर, बुधवार
20 मई 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री...

छग के बच्चों ने जय जोहार के साथ नॉर्वे में की पीएम मोदी का अभिनंदन

ओस्लो (नॉर्वे एजेंसी)। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नॉर्वे दौरे के दौरान भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर NACHA Nordic Chapter ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करते हुये पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। कार्यक्रम में बच्चों ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा धारण कर जय जोहार कहकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। यह दृश्य वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लिये विशेष आकर्षण का केंद्र रहा और सभी ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति की इस प्रस्तुति की सराहना की। इस सांस्कृतिक प्रस्तुति में अभिनव कुमार पांडेय (10 वर्ष) मूल निवासी बिलासपुर तथा चारु पांडेय (14 वर्ष) मूल निवासी भिलाई शामिल रहे। अभिनव ने पारंपरिक धोती-कुर्ता , पीले गमछे और सांस्कृतिक साफा पहनकर छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को दर्शाया। वहीं चारु ने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी शैली की साड़ी , जनजातीय आभूषण और पारंपरिक श्रृंगार के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा को प्रस्तुत किया। NACHA Nordic Chapter के सदस्यों ने बताया कि संस्था लगातार विदेशों में छत्तीसगढ़ी संस्कृति , भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के दौरान जय जोहार के साथ की गई यह प्रस्तुति छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का एक विशेष प्रयास था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि विदेश में रहकर भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है।

बच्चों की इस प्रस्तुति ने ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारतीय समुदाय को गौरवान्वित किया। बताते चलें कि पीएम मोदी पांच देशों के दौरे के चौथे चरण में दो दिवसीय प्रवास पर नॉर्वे पहुंचे हुये थे , यह 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक नॉर्वे यात्रा थी। नॉर्वे ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ़ मेरिट प्रदान किया है। ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ़ मेरिट का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी के लिये यह 32वां वैश्विक सम्मान है। ओस्लो में ऐतिहासिक यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय चर्चा वार्ता की और तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुये। ओस्लो सम्मेलन और यात्रा में भारत -नॉर्वे के बीच अपने द्विपक्षीय रिश्तों पर विस्तार से चर्चा हुई , दोनों देशों ने ग्रीन स्ट्रेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इसके तहत ब्लू इकोनॉमी , ग्रीन शिपिंग , स्वच्छ ऊर्जा , नवीकरणीय ऊर्जा और आर्कटिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाईयां देने पर सहमति बनी।? वहीं भारत और नॉर्वे के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर भी किये गये।

केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में आज बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक

नक्सल उन्मूलन अभियान में कांग्रेस सरकार ने नहीं की मददः अमित शाह

जगदलपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई, जिसमें विकास का रौडमैप तैयार किया गया। बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बस्तर में अब भय का माहौल समाप्त हो चुका है। हर जगह उत्साह, विश्वास नजर आ रहा है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि बस्तर अब नक्सल मुक्त हो गया है। कभी बंदूकों की साया में जीने वाला बस्तर आज चैन की सांस ले रहा है। उन्होंने कहा, नक्सल उन्मूलन अभियान में ढेर सारी नॉन बीजेपी सरकारों ने हमारा सहयोग किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया।

गृहमंत्री शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की चार महत्वपूर्ण तिथियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहली तारीख 13 दिसंबर 2023 थी, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में केंद्र का सहयोग नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण तारीख 24 अगस्त 2024 थी, जब सभी राज्यों के डीजीपी की बैठक में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प लिया गया। तीसरी तारीख 31 मार्च 2026 रही, जब देश से नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य तय किया गया। वहीं 19 मई 2026 को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास की नई परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया। बस्तर को अब देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम एवं गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद थे।गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद इसलिए पनपा क्योंकि इन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंचा, लेकिन विकास रुकने की सबसे बड़ी वजह भी नक्सलवाद ही था। उन्होंने बताया कि बस्तर जैसे विशाल क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए करीब 200 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जिनमें सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान तैनात रहे।

बस्तर में सुरक्षा कैंप बनेंगे 'सेवाडेरा', रोजगार को मिलेगा बढ़ावाः सीएम साय

रायपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर में आयोजित 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को राजधनी रायपुर लौट आए। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने पत्रकारों से चर्चा किया और बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों के सहयोग से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

सीएम विष्णुदेव साय ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर कहा कि चार राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य केंद्र के सहयोग के साथ टीम भावना में हमें विकास कार्य करना है। परिषद की बैठक सार्थक रही।इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार का सहयोग नहीं किया। केंद्र सरकार पहले से ही नक्सलवाद का अंत चाहती थी। बस्तर के सुरक्षा कैंपों को सेवाडेरा के रूप में विकसित किए जाने के सवाल पर सीएम साय ने कहा कि 200 सुरक्षा कैंपों में से 70 कैंपों में सेवाडेरा खोला जाएगा। इसकी शुरुआत आज एक कैंप से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सेवाडेरा के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार समेत अनेक फायदे मिलेंगे।

नीट पेपर लीक के बाद एक्शन

अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं : शिक्षामंत्री

नईदिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत त्रुटिरहित परीक्षा आयोजित करने की मांग की। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, प्रधान ने परीक्षा के संचालन में पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को व्यापक रूप से दूर किया जाए।

यह बैठक नीट-यूजी 2026 विवाद और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर जारी चिंताओं के बीच हुई है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्परीक्षा आयोजित करने से पहले पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई कमियों को व्यापक रूप से दूर किया जाना चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि पुन: नीट परीक्षा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित, सुचारू और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।

भाजपा में शामिल होंगे तेलंगाना के सीएम?

नईदिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर सियासी अटकलें लगने लगी हैं। शुरुआत पीएम मोदी की मुझसे ही जुड़ें वाली टिप्पणी से हुई थी और अब भाजपा के एक सांसद ने भी रेवंत रेड्डी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर दिया है।निजामाबाद से भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने दावा किया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगले शुभेंदु अधिकारी बन सकते हैं। धर्मपुरी अरविंद ने दावा किया कि रेड्डी राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि रेवंत वैसे ही पाला बदलेंगे, जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने छह साल पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते समय किया था।हालांकि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री चुनकर गलती की है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

प्रमुख समाचार

केजरीवाल सहित आप नेताओं को कोर्ट का अवमानना नोटिस

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (19 मई) को आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किया। अवमानना के आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए, पीठ ने कहा कि यह कार्यवाही इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 14 मई को दिए गए फैसले के आधार पर शुरू की गई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा की खंडपीठ ने सभी अवमानना के आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त, 2026 को सूचीबद्ध की। आप नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जो अदालत की गरिमा के विरुद्ध है।

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर केएमसी का नोटिस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक बदलाव के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। इन संपत्तियों में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव का आवास, 188ए हरीश मुखर्जी रोड, और दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड पर स्थित दो इमारतें, 119 और 121 शामिल हैं। ये नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए हैं। यह घटनाक्रम अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण से संबंधित आरोपों को लेकर मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। नगर निगम ने भवन निर्माण के दौरान सभी निर्माण मानदंडों और नगरपालिका नियमों का उचित पालन सुनिश्चित करने संबंधी जानकारी मांगी है। नगर निगम ने परिसर में किसी भी अवैध या अतिरिक्त निर्माण के संबंध में भी जानकारी मांगी है।

सांसद डोला सेन ने बंगाल में वोट चोरी का लगाया आरोप

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद डोला सेन ने कहा है कि पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हुए मतदान के नुकसान और अंतर का विश्लेषण करके कथित मत चोरी की तथ्य-जांच कर रही है। साथ ही, वे यह भी सवाल उठा रही हैं कि ईवीएम में कथित तौर पर 90 प्रतिशत से अधिक चार्ज कैसे रह गया और वोटों की दोबारा गिनती की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुकी है और आंतरिक समीक्षा के निष्कर्ष पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी। पत्रकारों से बात करते हुए सेन ने कहा कि हम दो मोर्चों पर तथ्य-जांच कर रहे हैं। पहला, मत चोरी की जांच करना, जिसके तहत हम यह पता लगा रहे हैं कि हमें कितने वोटों से नुकसान हुआ और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से कितने वोटों का अंतर रद्द किया गया; और दूसरा, यह समझना कि ईवीएम में 90% से अधिक चार्ज क्यों रह गया और वोटों की दोबारा गिनती की

पीएम मोदी पेमा खांडू पर चुप क्यों : कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को सवाल उठाया कि सीबीआई जांच जारी होने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अभी भी मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने हुए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि मुख्यमंत्री के परिवार को पिछले दस वर्षों में 1,270 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल, 2026 को सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को उन आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने का निर्देश दिया था कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार को जनवरी 2015 से दिसंबर 2025 तक 10 वर्षों में 1,270 करोड़ रुपये के ठेके सीधे हितों के टकराव में दिए गए थे। अपने पोस्ट में रमेश ने लिखा कि यह किसी निचली अदालत या उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। फिर भी मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। वे सार्वजनिक परिवहन एवं विकास मंत्री भी हैं।

यूपी विस चुनाव में गठबंधन जीत के आधार पर होगाः अखिलेश

लखनऊ। बंगाल में भाजपा की जीत के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी, इस पर सभी की नजर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब मंगलवार को एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मंच पर थे, तो उनसे इस बारे में सीधा सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वे इसकी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि हमारा विरोधी बहुत ताकतवर है, इसलिए हम रणनीति नहीं बताएंगे। 2027 में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि हमने पहले कई गठबंधन किए हैं। गठबंधन करने और चलाने का अनुभव हमारे पास है। समाजवादियों ने हमेशा दूसरों को लाभ दिया है, कभी धोखा नहीं दिया। जो गठबंधन आज हमारा है, वही आगे भी चलेगा। सवाल सीट का नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल सीट का नहीं, जीत का था। वही फॉर्मूला फिर से रहेगा। हमारा गठबंधन होगा और वह जीत के आधार पर होगा। सीट की संख्या के आधार पर नहीं होगा।

इंडिया की ताकत देखकर दंग रह गए यूरोपीय देश

प्रधानमंत्री मोदी की नार्वे यात्रा से पूरी दुनिया में मची हलचल

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नॉर्वे यात्रा ने भारत और नॉर्वे के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ओस्लो में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, निवेश और व्यापार के क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग का आधार भी माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस नई साझेदारी से जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित आपूर्ति शृंखला, समुद्री अर्थव्यवस्था और टिकाऊ विकास के क्षेत्रों में सहयोग को रणनीतिक दिशा मिलेगी। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्तोरे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता के बाद कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन दोनों देशों को उन ताकतों के खिलाफ साथ खड़ा होना होगा जो कूटनीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी का हथियार की तरह उपयोग करती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत और नॉर्वे की साझेदारी अब स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, हरित नौवहन और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के भविष्य के लिए निर्णायक कदम बताया।हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि चार दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया है। ऐसे समय में जब भारत पारंपरिक साझेदारों पर निर्भरता कम कर नए आर्थिक सहयोगियों की तलाश कर रहा है, नॉर्वे एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर रहा है। नॉर्वे का सरकारी पेंशन कोष दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु

निवेश कोषों में गिना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में उसने भारतीय बाजारों में निवेश लगातार बढ़ाया है।आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के मामले में नॉर्वे का हिस्सा 1.95 प्रतिशत था, जो 2025 तक बढ़कर 3.87 प्रतिशत हो गया। महामारी के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी तेजी आई है। भारत को हाल के वर्षों में नॉर्वे से लगभग 693 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। व्यापार के स्तर पर भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का नॉर्वे को निर्यात बढ़कर लगभग 472 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि आयात लगभग 635 मिलियन डॉलर रहा।प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को नया आयाम देना भी शामिल है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने नॉर्वे में पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, अपतटीय पवन ऊर्जा, कार्बन नियंत्रण, जैव आधारित प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सोमवार को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया गया। मोदी को यह सम्मान भारत-नॉर्वे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री को मिला 32वां विदेशी सम्मान है।इसके अलावा, भारत और नॉर्वे के अनुसंधान संस्थानों के बीच संयुक्त कार्यशालाओं, अनुसंधान परियोजनाओं और वैज्ञानिक आदान प्रदान की भी योजना बनाई गई है। विशेष रूप से समुद्री ऊर्जा और अपतटीय पवन ऊर्जा पर सहयोग भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को मजबूत करेगा और कार्बन तटस्थता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सतत विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था, समुद्री विज्ञान, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है।

जंगलों में पहुंचा स्वास्थ्य अमला, 771 ग्रामीणों का यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्वे

बीजापुर। बीजापुर जिले के दुर्गम ग्राम गमपुर में स्वास्थ्य विभाग ने यूनिवर्सल हेल्थ जांच सर्वेक्षण का सफल आयोजन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र डोडीतुमनार की टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद 771 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच एवं छानबीन की। जिले के अंदरूनी और दुर्गम क्षेत्र ग्राम गमपुर में स्वास्थ्य विभाग ने यूनिवर्सल हेल्थ स्क्रीनिंग सर्वेक्षण का आज सफल आयोजन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र डोडीतुमनार की स्वास्थ्य टीम ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना किया। सीमित संसाधनों के बावजूद टीम गमपुर गांव तक पहुंची और ग्रामीणों की जांच की।

टीम ने कुल 771 ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच एवं स्क्रीनिंग की। इस विशेष पहल के दौरान सामान्य स्वास्थ्य जांच के साथ कई बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई। इनमें मलेरिया, टीबी, एनीमिया और उच्च रक्तचाप शामिल थे। गर्भवती महिलाओं की भी विशेष स्क्रीनिंग की गई। सर्वेक्षण में 5 मलेरिया मरीजों की पहचान कर उनका तत्काल उपचार शुरू हुआ। 2 संभावित टीबी मरीजों और 1 हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान की गई। इन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। 1 उच्च रक्तचाप और 2 एनीमिया मरीजों को भी चिह्नित कर आवश्यक परामर्श व दवाएं उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीणों को साफ-सफाई, पोषण और नियमित जांच के महत्व के बारे में बताया। संक्रामक बीमारियों से बचाव संबंधी जानकारी भी दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार उनके गांव के समीप इतनी व्यापक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुई है।

इस अभियान से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान संभव हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। टीम के सतत प्रयासों से क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने में सफलता मिली है। यह अभियान ग्रामीण स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य विभाग जनसेवा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

धमतरी के दंपत्ति की अनोखी पहल

■ पति-पत्नी बच्चों को फल बांटकर ये संदेश दे रहे हैं कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें.

धमतरी। तुमनचंद साहू और उनकी पत्नी रंजीता साहू दोनों सरकारी नौकरी में हैं। दफ्तर का काम काज करने के बाद दोनों पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए दोनों बच्चों और ग्रामीणों के बीच फल बांटते हैं। फल बांटने के साथ ही ये दंपत्ति लोगों को फलों के पेड़ लगाने की सलाह भी देते हैं।

पति पत्नी का कहना है कि अगर पेड़ लगाएंगे तभी भविष्य में हम फल खा पाएंगे। तुमनचंद साहू और रंजीता साहू दोनों मगरलोड ब्लॉक के भैंसमुंडी गांव के रहने वाले हैं। फल बांटने वाले इस दपत्ति को अब इलाका का हर कोई जानता है। पति पत्नी दोनों बच्चों को ये समझाते हैं कि पर्यावरण और हरियाली का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही ये भी बताते हैं कि अगर पर्यावरण खराब होगा और पेड़ नहीं होंगे तो उसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ेगा। ये दंपत्ति बच्चों को हरियाली से जुड़े अभियान से भी जोड़ रहे हैं।

फल बांटने वाले दंपत्ति बताते हैं कि उनके घर में 20 से ज्यादा आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों में हर साल हजारों किलो आम फलता है। इसके अलावा उनके यहां 1100 से ज्यादा फलदार पेड़ हैं जिसमें आम, अमरूद, पपीता के पेड़ शामिल हैं। ये दंपत्ति फलों को बेचने के बजाए उनको बांटने का काम करते हैं।

तुमनचंद साहू कहते हैं कि अमरूद के सीजन में वे लगातार स्कूलों में जाकर बच्चों को अमरूद बांटते हैं। पिछले चार वर्षों में करीब 23 हजार किलो अमरूद विभिन्न स्कूलों तक पहुंचा चुके हैं। वहीं अब आम और पपीते के सीजन में समर कैंप, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांवों में पहुंचकर बच्चों को ताजे फल वितरित किए जा रहे हैं।

जैसे ही फलों का मौसम शुरू होता है, दोनों अपनी गाड़ी में टोकरियां भरकर प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों की ओर निकल पड़ते हैं। गांवों में पहुंचते ही बच्चे उत्साह के साथ उनका स्वागत करते हैं।

गौरेला पेंड्रा मरवाही में सफेद भालू के हमले में ग्रामीण घायल, इलाके में दहशत

जीपीएम। मंगलवार को पेंड्रा वन परिक्षेत्र में एक सफेद भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। इस घटना में ग्रामीण घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया और भालू को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आमाडाड गांव निवासी लालू ड्रावहर किसी काम से घघरा डेम की ओर जा रहा था। इसी दौरान जंगल से निकले सफेद भालू से उसका अचानक सामना हो गया। बताया जा रहा है कि भालू ने तुरंत लालू पर हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष हुआ।

लालू ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन वह घायल हो गया। घायल को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर और सामान्य है। भालू के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थिति को संभालने के लिए वन विभाग और पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारियों ने लोगों को भालू के करीब नहीं जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी।

बताया जा रहा है कि भालू पानी और भोजन की तलाश में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाके की ओर पहुंचा था। गर्मी बढ़ने और जंगलों में पानी की कमी के कारण जंगली जानवर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। हमला करने के बाद भालू घघरा क्षेत्र से आमाडाड, बसंतपुर होते हुए नवागांव की ओर बढ़ गया। वन विभाग द्वारा भालू की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल या सुनसान क्षेत्रों में न जाएं।

अवैध मुरूम उत्खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहन जब्त

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर खनिज विभाग की जिला उड़नदस्ता टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाकर 2 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर वाहन जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से अवैध खनिज करने वालों में हड़कंप मच गया है। खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, टिकरकला क्षेत्र में जांच के दौरान एक जेसीबी वाहन को अवैध खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा गया। वहीं रूमगा क्षेत्र में खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर वाहन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया गया। इसके अलावा कोटमी क्षेत्र में मुरुम का अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया। इसी दौरान अवैध रेत परिवहन में लगे एक अन्य ट्रैक्टर वाहन को भी पकड़ा गया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए आने वाले दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की

अबूझमाड़ के ईरकभट्टी में शुरू हुआ सेवा सेतु केंद्र

गांव में ही मिलेंगी 441 डिजिटल सेवाएं

नारायणपुर। अबूझमाड़ क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ओरछा विकासखंड के ईरकभट्टी स्थित पुलिस कैंप में सेवा सेतु केंद्र की शुरुआत की गई। इस पहल से अब ग्रामीणों को शासकीय दस्तावेजों और ऑनलाइन सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं जाना पड़ेगा।

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन संचालक, जल शक्ति मंत्रालय कमल किशोर सोन अबूझमाड़ के इस दूरस्थ गांव पहुंचे और यहां के रहने वाले ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं और सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ईरकभट्टी में स्थापित सेवा सेतु केंद्र का उद्देश्य अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक शासन की डिजिटल सेवाओं को पहुंचाना है।कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के उन्नत संस्करण 'सेवा सेतु' के माध्यम से आम लोगों तक पारदर्शी और सुगम नागरिक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सेवा सेतु पोर्टल पर 441 शासकीय सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें 54 नई सेवाएं और 329 री-डायरेक्ट सेवाएं शामिल हैं। अब ग्रामीण आधार कार्ड अपडेट, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज गांव के समीप ही बनवा सकेंगे। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण सेवा सेतु केंद्र पहुंचे और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लिया। रितेश पोटाई सहित कई ग्रामीणों के आधार अपडेट और अन्य डिजिटल कार्य मौके पर ही किए गए। गांव में पहली बार ऐसी सुविधा मिलने से ग्रामीणों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला।

एमपी से मरवाही पहुंचा चार हाथियों का दल

गौरेला पेंड्रा मरवाही । गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन क्षेत्र में एक बार फिर चार हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है।गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन क्षेत्र में एक बार फिर चार हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार हाथियों का समूह मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले से गुजरनाला पार करते हुए मरवाही वन परिक्षेत्र एवं वन मंडल के सिवनी परिक्षेत्र अंतर्गत दैईगवा गांव के छुलहनी जंगल में पहुंचा। यहां कुछ समय तक आराम करने के बाद हाथियों का दल सिवनी गांव को पार करते हुए मरवाही क्षेत्र के पथरी गांव की ओर बढ़ गया। हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई और लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।हालांकि हाथियों के द्वारा किसानों की खेतो में खड़ी फसलों को भी काफी नुकसान पहुचाया गया है।।वही मरवाही वन मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रभावित गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को सतर्क एवं सावधान रहने की समझाइश दी जा रही है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के नजदीक जाने की कोशिश न करें और न ही उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान करें। विभाग ने विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को हाथियों के आसपास नहीं जाने देने की बात कही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुर्घटना की आशंका अधिक रहती है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

करहि हत्याकांड का अब तक नहीं मिला कोई सुराग

जांजगीर चांपा। बिर्रा थाना इलाके के करहि गांव में दिनदहाड़े आयुष की हत्या हो गई थी। घर में घुसकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अबतक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने गांव में चौकी स्थापित कर दी। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय का कहना है कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन हंट शुरू किया गया है, जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि कुछ रसूखदारों पर संदेह है, जिनसे पूछताछ के निर्देश दिए गए हैं। करहि सक्ती के राजस्व जिले में आता है। पर इस गांव की गिनती जांजगीर चांपा जिले में की जाती है। दोनों जिलों से करहि गांव का संपर्क है, बावजूद इसके इस गांव पर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता। एसपी जरूर ये कहते हैं कि करहि गांव से महानदी का किनारा लगता है। जहां महानदी से अवैध तरीके से रेत का खनन होता है। रेत खनन को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक खुद ये स्वीकार करते हैं।

फार्म हाउस में जुए खेलते मालिक समेत 8 गिरफ्तार

बिलासपुर। गतौरी स्थित वृंदावन ग्रीन फार्म हाउस में बड़े स्तर पर जुआ खेले जाने की सूचना बिलासपुर पुलिस को मिली। जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर सोमवार देर रात मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान फार्म हाउस के अंदर कई लोग जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने तत्काल सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में ओम नगर के रहने वाले रोशन सिंह, राजीव गांधी चौक के रहने वाले मुन्ना गोयल,दीनदयाल कॉलोनी मंगला के विकास सिंह, विद्या नगर तारबहार के फार्म हाउस संचालक मनीष शर्मा, नीरज शर्मा, रामा लाइफ सिटी सकरी निवासी दीपक अग्रवाल, तखतपुर के चंद्रकिशन अग्रवाल और तिफरा नया बस स्टैंड के रहने वाले मयंक सोनकर (20) शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख 80 हजार रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन और 5 चार पहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामानो की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले मे कोनी पुलिस कार्रवाई कर रही है।

रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने एसपी ने बनाई टीम

जांजगीर चांपा। जिला के पुलिस कप्तान एक्शन मोड़ में आ गए है। रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इलीगल माइनिंग टास्क फोर्स की गठन किया है, जो 24 घंटे काम करेगी। पहले दिन ही नवागढ़ और शिवरीनारायण क्षेत्र में खनिज और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ पहली एफआईआर भी दर्ज की है। जिले में हसदेव नदी और महानदी में रेत माफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए अलग अलग रेत घाटों से चैन माउन्टेन, जेसीबी मशीन से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। हाइवा में रेत बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा जिलों में सप्लाई की जा रही है। खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद भी रेत माफिया इस कारोबार को लगातार जारी रखे हैं।जांजगीर एसपी विजय पांडेय ने बताया कि वहीं कई बार खनिज माफिया आपस में उलझ कर लॉ एंड आर्डर की स्थिति निर्मित कर देते हैं।

दिल्ली-यूपी से पकड़ाए 7 साईबर ठगी के आरोपी

कोंडागांव। जिले की फरसगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तरप्रदेश से साइबर ठगी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तलाश पिछले 3 महीनों से की जा रही थी। फरसगांव निवासी शंकरलाल राणा से आरोपियों ने अलग-अलग मोबाइल नंबरों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब 29.69 लाख रुपये की ठगी की। मामले में थाना फरसगांव में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा के निर्देशन और एसडीओपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने 10 दिनों तक दिल्ली में रहकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के सदस्य खुद को बीमा लोकपाल परिषद का अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे। वे बीएसई स्टॉक एक्सचेंज में फंड या बीमा राशि फंसी होने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर रकम जमा करवाते थे। गिरोह के सदस्य कीपैड मोबाइल और फर्जी सिम का उपयोग कर पुलिस से बचते थे।

ग्रामीणों ने डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग

धमतरी। जिले के सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी में वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण आज धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम गांव पहुंचकर लोगों को जबरन घरों से उठाकर ले गई, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। वहीं वन विभाग की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों को ग्रामीणों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। दरअसल पूरा मामला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ग्राम जैतपुरी का है, जहां गरियाबंद डीएफओ अपनी टीम के साथ कथित अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि धक्का-मुक्की के दौरान डीएफओ बाल-बाल बचे। ग्रामीणों का कहना है कि इस दौरान गांव के कई लोगों को चोटें भी आई है।

20 मई को केमिस्ट हड़ताल से पहले धमतरी प्रशासन सतर्क

धमतरी। 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। मरीजों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला औषधि विक्रेता संघ के प्रस्तावित एक दिवसीय बंद को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी शासकीय अस्पताल, निजी अस्पतालों की फार्मेसी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र और श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नियमित रूप से खुले रहेंगे। साथ ही इमरजेंसी सेवाएं, प्रसूति सेवाएं और आकस्मिक उपचार भी पहले की तरह संचालित होते रहेंगे। कलेक्टर ने सहायक औषधि नियंत्रक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकीय सामग्री और स्वास्थ्य उत्पादों का पर्याप्त भंडारण बनाए रखा जाए ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को परेशानी न हो। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्था या अधिकृत मेडिकल स्टोर से संपर्क करें। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के परिजनों से अपील की है कि नियमित उपयोग में आने वाली दवाइयां डॉक्टर की पर्ची के आधार पर पहले से ही प्राप्त कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला प्रशासन ने दवा व्यापारियों और मेडिकल स्टोर संचालकों से भी जनहित को प्राथमिकता देते हुए जीवन रक्षक दवाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश पर नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

■ एमसीबी जिले में नशा और बिना अनुमति संचालित क्लीनिकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है.

एमसीबी। कलेक्टर संतन देवी जांगड़े के निर्देश पर एसडीएम भरतपुर ने मेडिकल स्टोर्स और संदिग्ध क्लीनिक्स की जांच के लिए एक टीम गठित की। इसके बाद रामगढ़ और जनकपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाकर मेडिकल दुकानों, क्लीनिकों और दवा भंडारण स्थलों की गहन जांच की गई। जनकपुर क्षेत्र में मेडिकल नशे के फैलते जाल को लेकर मीडिया में दिखाई खबरों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और मामले में तुरंत संयुक्त जांच अभियान चलाया। जांच टीम ने मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स एवं प्रतिबंधित दवाओं की खरीदी बिक्री से जुड़े दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। प्रशासन ने विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया कि कहीं बिना अनुमति नशीली दवाओं का अवैध कारोबार तो नहीं चल रहा और न ही किसी प्रकार की अवैध चिकित्सा गतिविधि संचालित हो रही हो। निरीक्षण के दौरान रामगढ़ स्थित मंजू मेडिकल स्टोर्स और उसके समीप संचालित एक अवैध क्लीनिक में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर और क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जांच अभियान के दौरान जनकपुर क्षेत्र की पांच अन्य दवा दुकानों में भी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद संबंधित संचालकों को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जिन दुकानों को नोटिस जारी किया गया उनमें - प्रदीप मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर, आलिया मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर, केसरवानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, सिंह मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर, न्यू गुप्ता मेडिकल स्टोर्स, जनकपुर, प्रशासन की दो टूक चेतावनी ,जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैधानिक अनुमति चिकित्सा गतिविधियों का संचालन, प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री, नशीली दवाओं का दुरुपयोग अथवा औषधि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबारियों और फर्जी क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया है।जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं बिना पंजीयन संचालित क्लीनिक, अवैध मेडिकल गतिविधियां, प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री या किसी प्रकार की संदिग्ध चिकित्सा गतिविधि दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का किया आत्मीय स्वागत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को बस्तर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें राजकीय गमछा भेंट कर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उन्हें सम्मान दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन आज बस्तर में किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय, विकास और प्रशासनिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बीच विभिन्न समसामयिक मुद्दों, राज्यों के बीच आपसी समन्वय तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सुशासन, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य देश में सर्वाधिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है। विभाग केवल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पत्तों की खरीदी करता है। कटे-फटे और निम्न गुणवत्ता के पत्ते रिजेक्ट किए जाते हैं। यह जानकारी प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने दिया है। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ने बताया कि रिजेक्ट तेंदूपत्तों पर संग्राहकों का स्वामित्व है। वे अपनी वनोपज को निजी स्तर पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह वैध व्यापारिक प्रक्रिया है, इसे तस्करी नहीं कहा जा सकता। 18 मई 2026 तक सुकमा में 84 हज़ार 382 मानक बोरा यानी लक्ष्य का 77.84: संग्रहण हो चुका है। कोन्टा क्षेत्र की 5 समितियों में 100: से अधिक संग्रहण हुआ है। राज्य में कुल 11.64 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। 46 हज़ार 625 संग्राहक जुड़े हैं, जो पिछले वर्ष से अधिक है। ओडिशा सीमा से लगे क्षेत्रों में वन विभाग की सघन गश्त और रात्रिकालीन पेट्रोलिंग जारी है। अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। कोरिरास सहित किसी भी फड़ में तेंदूपत्ता सड़ने या दीमक लगने की स्थिति नहीं है। संग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी है और भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है।

भिलाईखुर्द दुर्घटना मामले की संयुक्त जांच दल ने की मौके पर जांच

रायपुर। बलरामपुर जिले के तहसील राजपुर अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द में स्थित एक क्रशर प्लांट में कार्यरत मजदूर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। घटना के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर मौके पर विस्तृत जांच की गई। जांच के दौरान खनिज विभाग के अमले एवं नायब तहसीलदार द्वारा संबंधित क्रशर मशीन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। साथ ही जिला श्रम अधिकारी तथा सहायक संचालक इंडस्ट्रीज एंड हेल्थ सेफ्टी द्वारा श्रम एवं औद्योगिक सुरक्षा संबंधी विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मामले में जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित क्रशर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आज घरजियाबथान और कुसुमताल में आयोजित होंगे जनसमस्या निवारण शिविर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जशपुर जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन निरंतर जारी है। इस अभियान के माध्यम से शासन और प्रशासन ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और मांगों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में 20 मई 2026 को जशपुर जिले के पत्थलगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम घरजियाबथान तथा कांसाबेल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कुसुमताल में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आसपास के ग्रामीण अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। घरजियाबथान शिविर में खरकट्टा, खारढोढ़ी, घरजियाबथान, चंदागढ़, चंदरपुर, डुमरबहार, तमता, तिरसोंठ, सुरजगढ़, शेखरपुर, रघुनाथपुर, बिलडेगी, बटुराबहार, बनगांव-बी, बालाझर, कुड़केलखजरी एवं पंडरीपानी के ग्रामीण शामिल होंगे। इसी प्रकार कुसुमताल शिविर में नकबार, बटईकेला, साजापानी, चिडोरा, कुसुमताल, खुटेरा, खारपानी, सागीभावना, कोडलिया, डांडपानी, सिहारबुड़, लमडांड, पोंगरो एवं कांसाबेल के ग्रामीण अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र मामलों का मौके पर निराकरण किया जाएगा।

11 पूर्व सरपंच जाएंगे जेल

एसडीएम कोर्ट ने जारी किया आदेश

रायपुर। रायपुर के अभनपुर विकासखंड के 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से 30 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। यह आदेश उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि का गबन और उस राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश का उल्लंघन करने पर जारी किया गया है।

30 दिनों का जेल भेजने का आदेश जारी किए जाने के पहले उन सभी पूर्व सरपंचों को न्यायालय एसडीएम अभनपुर की ओर से मांग नोटिस जारी करने के साथ ही उनकी चल/अचल संपति जब्त करने की कार्रवाई भी गई थी, लेकिन इसके बावजूद संबंधित राशि चुकाने के लिए पर्याप्त साधन होने के बाद भी संबंधित पूर्व सरपंचों द्वारा गबन की गई शासकीय राशि जमा करने में हीलाहवाली किया जा रहा था।

इतना ही नहीं एसडीएम न्यायालय

द्वारा सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें उनके कृत्य के लिए क्यों न जेल भेजा जाए ? भी पूछा गया था, लेकिन किसी भी पूर्व सरपंच ने नोटिस का संतोषजनक और वैधानिक उत्तर नहीं दिया। आखिरकार 18 मई को एसडीएम न्यायालय द्वारा सभी को 30 दिन या फिर जब तक वे संबंधित राशि जमा नहीं कर देते हैं, तब तक सिविल जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश की तामिली करते हुए संबंधित पूर्व सरपंचों को जेल भेजने का पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर के अधीक्षक को भी इस आशय का पत्र भेजा गया है ।

जिन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध इस आशय का आदेश जारी किया गया है उनमें सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंठ) 1 लाख 96 हजार रुपए, गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रु) 80 हजार रुपए, गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए, तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रूपए, रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए, थनवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए, सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए, धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए, राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए, तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए और सेवेंद्र तारक (पूर्व सरपंच तोरला) 1 लाख 56 हजार 915 रुपए शामिल हैं । एसडीएम अभनपुर ने बताया कि अगर संबंधित पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा ।

21 मई को पीपीएचटी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 21 मई 2026 को पीपीएचटी और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजधानी रायपुर में इन परीक्षाओं के लिए 12 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, जहां करीब दो हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। व्यापम से मिली जानकारी के अनुसार पीपीएचटी-26 परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित होगी। वहीं पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी पीबीएन-26 परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संपन्न कराई जाएगी।

दोनों परीक्षाओं में कुल 1,954 परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। परीक्षा संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गोपनीय प्रश्नपत्र और अन्य सामग्री का वितरण 21 मई की सुबह 7:30 बजे जिला कोषालय परिसर से किया जाएगा।

रायपुर में शासकीय जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर

सड्डू की 1.5 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त

रायपुर। राजधानी रायपुर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने ग्राम सड्डू स्थित शासकीय घास भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए करीब 1.5 एकड़ जमीन को कब्जामुक्त कराया।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार तहसील रायपुर के राजस्व पटवारी हल्का नंबर-44 अंतर्गत खसरा नंबर 8/1 और 8/2 की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। जांच में सामने आया कि चंद्रशेखर यादव द्वारा उक्त जमीन पर अतिक्रमण किया गया था।

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और निर्धारित प्रक्रिया के तहत कब्जा हटाया गया। प्रशासन ने जमीन को मुक्त कर पुनः शासकीय नियंत्रण में ले लिया है।

अभियान के दौरान तहसीलदार राममूर्ति दीवान, नायब तहसीलदार सौरभ कश्यप, राजस्व निरीक्षक, पटवारी और नगर निगम की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

राजधानी में बिजली गुल और लो-वोल्टेज की समस्या, कांग्रेसियों ने घेरा सीएसईबी दफ्तर

जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

रायपुर। राजधानी रायपुर में बिजली गुल और लो-वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेसियों ने मंगलवार को गुढ़ियारी स्थित बिजली दफ्तर का घेराव किया। कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएसईबी के चीफ इंजीनियर ऑफिस में प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएसईबी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।

प्रदर्शन के दौरान बिजली बिल की बढ़ोतरी, लो-वोल्टेज और आए दिन लाइट बंद होने की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का भी फूटा गुस्सा फूटा। कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से गुढ़ियारी और रामनगर के कई घरों में बिजली बंद है। यहां के लोग बिजली ऑफिस में फोन लगाते हैं, लेकिन यहां के अधिकारी फोन नहीं उठाते। इससे आम जनता को बड़ी परेशानी होती है। पिछली बार भी हम बिजली ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बिजली की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है। एक बार फिर आज हम लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव कर जल्द बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग की है।

सुबोध हरितवाल ने कहा कि मैं अपने बचपन से सुनते आ रहा हूं कि मेंटेनेंस कार्य चल रहा है। जल्दी बिजली आ जाएगी, लेकिन 40-42 साल से यह समस्या बनी हुई है। आज तक बिजली बंद की समस्या ठीक नहीं हुई है। वहीं पूरे मामले में बिजली ऑफिस के अधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया है। जहां-जहां लाइट की समस्या है हमारे अधिकारी वहां पहुंचकर लाइट को बना चुके हैं। आगे जो भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी बिजली विभाग तत्परता से वहां पर काम करेगा।

जहां कभी डर था, वहां अब विकास की नई पहचान

रायपुर। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाला यह गांव अब प्रशासन और जनता के मजबूत विश्वास का प्रतीक बन गया है। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड का ग्राम पुवर्ती अब बदलाव और विकास की नई मिसाल बनकर सामने आया है। जनगणना कार्य के प्रथम चरण में पुवर्ती सुकमा जिले का पहला ऐसा गांव बना, जहां सबसे पहले जनगणना कार्य पूरा किया गया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर श्री अमित कुमार ने कलेक्टर कक्ष में प्रगणक एवं सहायक शिक्षक श्री जवाराम पटेल को सम्मानित किया। श्री पटेल ने मात्र तीन दिनों में गांव का जनगणना कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।

श्री जवाराम पटेल ने बताया कि उनके कार्यक्षेत्र में लगभग 950 से अधिक आबादी और 234 मकान शामिल थे। गांव में 2 आंगनबाड़ी केंद्र और 1 स्कूल संचालित है। जनगणना के दौरान स्थानीय गोंडी भाषा समझने में कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती नहीं बल्कि सेवा का अवसर मानते हुए कार्य जारी रखा। उन्होंने स्थानीय शिक्षकों के सहयोग से गांव की सामाजिक व्यवस्था को समझा और हर परिवार तक पहुंचकर सर्वे कार्य पूरा किया। सीमित संसाधनों और भाषा संबंधी कठिनाइयों के बावजूद उनकी मेहनत और समर्पण से कार्य समय पर पूर्ण हो सका। कलेक्टर ने कहा कि श्री जवाराम पटेल का समर्पण, साहस और जिम्मेदारी के प्रति निष्ठा अन्य जनगणना कर्मियों के लिए प्रेरणादायक है।

राजधानी में एक और लिफ्ट कांड!

एसीएस के बाद अब भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी फंसे

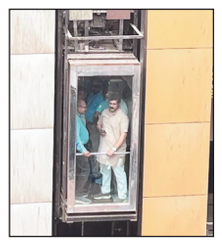

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक बार फिर लिफ्टकांड हो गया। रजबंधा मैदान स्थित निजी कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को अचानक लिफ्ट खराब हो गई, जिसमें भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी समेत 7 लोग अंदर लगभग 15 मिनट तक फंसे रहे। मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह सुरक्षा गार्ड ने दरवाजे खुलवाकर उन्हें बाहर निकाला। घटना का वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कॉम्प्लेक्स प्रबंधन पर ठिकरा फोड़ा। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि इस कॉम्प्लेक्स में पहले भी लिफ्ट खराब होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कभी बुजुर्ग तो कभी महिलाएं यहां लिफ्ट में फंस जाती हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक, निजी कॉम्प्लेक्स में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी और अन्य लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। इस दौरान लिफ्ट अचानक बंद हो गया। सभी ने बार-बार अलार्म और फोन से मदद मांगने की कोशिश की, हालांकि तत्काल किसी प्रकार की तकनीकी सहायता नहीं मिल सकी। बाद में कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों ने मशक्कत कर लिफ्ट का गेट खुलवाया। इसके बाद सभी सुरक्षित बाहर निकल गए।

बता दें कि रायपुर की कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिफ्ट इन दिनों चर्चा में हैं। पिछले दिनों करेंसी टॉवर की लिफ्ट में एसीएस यानी असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी (एसीएस) ऋचा शर्मा लिफ्ट में फंस गईं। यह घटना सुबह करीब 6:30 बजे की थी, जब एसीएस ऋचा शर्मा लगभग 10 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसी रहीं। वह लिफ्ट से जिम जा रही थी, तभी घटना हुई। मामले में कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए थे। जांच में सामने आया था कि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने पर डीजल जनरेटर के ऑटोमैटिक चेंजओवर सिस्टम में तकनीकी खराबी उत्पन्न हुई, जिसके कारण यूपीएस भी प्रभावित हुआ और लिफ्ट को निरंतर विद्युत आपूर्ति नहीं मिल सकी।

कोलियारी समाधान शिविर में दूर हुईं ग्रामीणों की समस्याएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना सुशासन तिहार 2026 के तहत जनपद पंचायत नारायणपुर के ग्राम कोलियारी में आयोजित समाधान शिविर सफल रहा। आम जनता की समस्याओं को उनके घर-द्वार पर ही सुलझाने के उद्देश्य से लगाए गए इस शिविर में प्रशासन द्वारा मौके पर ही कई आवेदनों का त्वरित निराकरण कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में सुशासन तिहार का व्यापक जन-समस्या निवारण अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना और उनकी शिकायतों का ऑन-स्पॉट समाधान सुनिश्चित करना है।

कोलियारी के इस शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 176 आवेदन दर्ज किए गए। आंकड़ों के लिहाज से सबसे अधिक 58 आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुए। इसके बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 41, कृषि विभाग में 17 और विद्युत विभाग में 13 आवेदन जमा किए गए। इसी तरह ऊर्जा/क्रेडा के 9,पीएमई के 8, मत्स्य व परिवहन के 6-6, आरईएस के 5,जल संसाधन के 3,उद्योग, राजस्व व आदिम जाति कल्याण के 2-2,महिला एवं बाल विकास, वन, शिक्षा व सहकारिता के 1-1 आवेदन प्राप्त हुए।

शिविर में संवेदनशील पहल करते हुए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 21 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपये कुल 1 लाख रुपये की स्वेच्छानुदान राशि का चेक प्रदान किया गया। इसके साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी को सुगम बनाते हुए खाद्य विभाग द्वारा मौके पर ही वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

शिविर में न केवल समस्याओं का समाधान हुआ, बल्कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे तौर पर हितग्राहियों को सौंपा गया। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 04 हितग्राहियों को उनके सपनों के प्रधानमंत्री आवास की चाबियां सौंपी गईं।

दिव्यांगता को नहीं बनने दिया बाधा, रामकली हल्बा बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

- **सुशासन तिहार 2026 में समयपूर्व ऋण चुकाने और सफल व्यवसाय संचालन के लिए हुईं सम्मानित**

रायपुर। दिव्यांगता को नहीं बनने दिया बाधा, श्रीमती रामकली हल्बा बनीं आत्मनिर्भरता की मिसालछत्तीसगढ़ में शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं ऋण योजनाएं दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम बिहरीकला की निवासी श्रीमती रामकली हल्बा की, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सफलता की नई मिसाल कायम की है।

अस्थिबाधित दिव्यांग श्रीमती रामकली हल्बा को वर्ष 2011 में समाज कल्याण विभाग से 50 हजार रूपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस सहायता राशि से उन्होंने अपने गांव में किराना दुकान का व्यवसाय प्रारंभ किया। शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ यह छोटा व्यवसाय धीरे-धीरे मेहनत और ईमानदारी के बल पर आगे बढ़ता गया।

श्रीमती रामकली बताती हैं कि आर्थिक कठिनाइयों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नियमित मेहनत और ग्राहकों के विश्वास के कारण उनका व्यवसाय लगातार बढ़ता गया। आज उनकी किराना दुकान गांव में अच्छी तरह स्थापित हो चुकी है और वे अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने लगभग डेढ़ से दो वर्षों के भीतर ही पूरा ऋण चुका दिया। समयावधि से पहले ऋण अदायगी करने पर उन्हें 3,750 रूपये की उत्थान सब्सिडी भी प्राप्त हुई।

श्रीमती रामकली हल्बा की सफलता आज क्षेत्र के लोगों, विशेषकर दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि अवसर और संकल्प दोनों साथ हों तो कोई भी कठिनाई सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती।

सुशासन तिहार 2026 के अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा श्रीमती रामकली हल्बा को समयपूर्व ऋण चुकाने, सफल व्यवसाय संचालन एवं आत्मनिर्भर बनने पर सम्मानित भी किया गया। यह सम्मान उनके संघर्ष, मेहनत और उपलब्धियों की पहचान बना।

गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञापन देने निकले कांग्रेसी

- **पुलिस ने बीच रास्ते में रोका, दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना**

रायपुर। बस्तर के स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि दल आज जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे थे, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

दरअसल कांग्रेसी नेताओं ने जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर स्थानीय मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं का दल राजीव भवन से बैठक स्थल के लिए रवाना हुआ, लेकिन बीच रास्ते में ही मिताली चौक में कांग्रेस के दल को पुलिस ने बैरिकेटिंग के जरिए रोक दिया।

इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार बस्तर के हितों का ध्यान नहीं रख रही। कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल को केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात नहीं करने दिए जाने पर दीपक बैज ने नाराजगी जताई।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड रायपुर (छ.ग.)

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "ए" में प्रतिशत दर पर कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:- (तृतीय आमंत्रण)

क्र.	निविदा आमंत्रण क्र. / दिनांक सिस्टम नं.	जिला	योजना का नाम	निविदा की अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1	1/15-05-2026 191004	रायपुर	Construction of E/M Circle Office Building for Public Health Engineering E/M Circle Raipur, District Raipur	60.90

Important Events and Time Schedule - Bid Start Date 18-05-2026, Pre Bid meeting date 25-05-2026, Bid Due Date 01-06-2026, PHY Doc. Submission last Date 03-06-2026, PQ Document Download Date 03-06-2026

नोट :- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तों, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेबपोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in में उक्त निविदा दिनांक 16.05.2026 से देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना
खण्ड रायपुर (छ.ग.)

जी-262700791/3

सनातन विरोध की राजनीति पर जनता का लोकतांत्रिक प्रहार

प्रेम शुक्ल

सोचिए उस माली की मूर्खता को, जो उस वृक्ष की जड़ें काटने निकलता है, जिसकी छांव में वह स्वयं पला-बढ़ा हो। भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। एक तरफ वह सनातन, जो हजारों वर्षों की तपस्या, त्याग और ज्ञान की नींव पर खड़ा है, जो इस देश की सांसों में रचा-बसा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनेता, जिन्होंने वोट की भूख में अंधे होकर इसी सनातन को अपशब्द कहना, हिंदू आस्था को कोसना और भारत की आत्मा को ललकारना अपनी राजनीति का हथियार बना लिया। उन्हें लगा, हिंदू समाज बिखरा हुआ है, आस्था को रौंदते रहो, कोई प्रतिकार नहीं होगा। लेकिन यह देश गीता की भूमि है। यहां लिखा है-'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥' जब-जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब एक शक्ति जागती है। इस बार वह शक्ति किसी रणक्षेत्र में नहीं, मतपेटी में जागी और जनता ने वह जवाब दिया, जिसकी इन नेताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु की राजनीति से सामने आया, जहां द्रमुक नेताओं ने खुले मंचों से सनातन धर्म को 'डेंगू और मलेरिया' जैसी बीमारी तक कह दिया। द्रमुक के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता ए. राजा ने इससे भी आगे बढ़कर सनातन की तुलना 'एच.आई.वी.' और 'कुष्ठ रोग' जैसी बीमारियों से कर दी। द्रमुक के प्रवक्ता कॉन्स्टेंटाइन रवींद्रन ने सनातन धर्म को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की 'बुद्धि की कमी' का कारण बता दिया और अब इस सनातन-विरोधी राजनीति में एक नया और चिंताजनक अध्याय जुड़ गया है। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टी.वी.के. ने हाल ही में सरकार बनाई लेकिन सत्ता की कुर्सी गर्म होने से पहले ही इस दल के नेताओं ने सनातन के विरुद्ध अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। टी.वी.के. के विधायक और तमिलनाडु मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष वी.एम.एस. मुस्तफा ने खुले मंच से घोषणा की, 'सनातन को समाप्त करने के लिए ही हम रणक्षेत्र में उतरे हैं।' जो पार्टी अभी-अभी जनता का विश्वास लेकर सत्ता में आई, उसके नेता पहले ही दिन से सनातन को मिटाने की भाषा बोलने लगें, यह तमिलनाडु की जनता के साथ विश्वासघात है और पूरे देश के लिए एक कड़ी चेतावनी। देश ने यह सब देखा और समझ लिया कि यह केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर करने की सुनियोजित मानसिकता है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने दशकों तक नास्तिकता के नाम पर सनातन परंपराओं का वैचारिक विरोध किया। इनके नेताओं और समर्थक बुद्धिजीवियों ने हिंदू रीति-रिवाजों, मंदिर परंपराओं और आध्यात्मिक आस्थाओं को बार-बार पिछड़ेपन, असमानता और सामाजिक उत्पीडन् से जोडने् का प्रयास किया। बिहार में रामचरितमानस जैसे पूजनीय ग्रंथ पर आर.जे.डी. से जुड़े नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणियां की गईं। यह केवल एक पुस्तक पर टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना पर हमला था, जो भारत को जोड़ती है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं को लगा कि हिंदू समाज चुप रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में जनता सब देखती है और समय आने पर जवाब भी देती है। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों से जुड़े कई नेताओं ने भी समय-समय पर हिंदू प्रतीकों और धार्मिक नारों पर सवाल उठाए। इस हिंदू-विरोधी नैरेटिव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर भगवान राम को मात्र एक 'पौराणिक पात्र' बता दिया और करोड़ों हिंदुओं के 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हुए राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को 'नाच-गाना' कहकर उसका भद्दा मजाक उड़ाया।

चीन-अमेरिका निकटता से भारत के सामने वैश्विक चुनौतियाँ

ललित गर्ग

दुनिया एक बार फिर ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहाँ दो महाशक्तियों-अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते संवाद, आपसी मुलाकातों और कूटनीतिक समीकरणों को केवल द्विपक्षीय संबंधों के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संवाद और संभावित समझौतों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक वर्ग इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए राहतकारी कदम मान रहा है, क्योंकि इससे बढ़ती महंगाई, व्यापारिक अवरोधों और युद्धजन्य संकटों में कमी आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निकटता भविष्य में एक ऐसे विश्व संरचना को जन्म दे सकती है जहाँ दुनिया की दिशा पुनः कुछ महाशक्तियों के हाथों में सिमट जाए और विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँ। भारत जैसे देशों के लिए यह परिस्थिति अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है।

आज अमेरिका और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 44 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करते हैं। विश्व व्यापार, तकनीकी विकास, ऊर्जा बाजार, वैश्विक निवेश, वित्तीय संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों पर इन दोनों देशों का गहरा प्रभाव है। ऐसे में इनके संबंधों में किसी भी प्रकार का बदलाव पूरी दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, टैरिफ विवाद, तकनीकी प्रतिबंध और ताइवान से जुड़े तनावों ने विश्व अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाला। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएँ टूट गईं, रूस-यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संकट बढ़ाया और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। इन परिस्थितियों में यदि अमेरिका और चीन संवाद और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बल मिल सकता है।

विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने से सबसे पहले वैश्विक बाजारों को राहत मिलेगी। निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, तकनीक तथा विनिर्माण क्षेत्रों में लागत घट सकती है। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण संभव है। किंतु यह केवल तस्वीर का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि यदि दोनों महाशक्तियाँ वैश्विक व्यापारिक नियमों और आर्थिक नीतियों को अपने हितों के अनुसार तय करने लगें तो छोटे देशों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। दुनिया पहले भी उपनिवेशवाद और आर्थिक नियंत्रण की राजनीति देख चुकी है, अब आशंका यह है कि कहीं आर्थिक वैश्वीकरण का नया स्वरूप महाशक्तियों के संयुक्त वर्चस्व में परिवर्तित न हो जाए। इसी संदर्भ में जी-2 यानी अमेरिका और चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विश्व धीरे-धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था से हटकर दो महाशक्तियों के प्रभाव वाले ढाँचे की ओर बढ़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक नीतियों, व्यापारिक समझौतों और सुरक्षा संबंधी निर्णयों में छोटे देशों की भूमिका सीमित हो सकती है। यह स्थिति भारत जैसे देशों के लिए विशेष चिंता का विषय है क्योंकि भारत हमेशा से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और सामूहिक वैश्विक नेतृत्व का समर्थक रहा है।

भारत की स्थिति यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिकी खेमे में है और न ही चीन के प्रभाव क्षेत्र में। भारत ने लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ भारत के रक्षा, तकनीकी और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका है। दूसरी ओर चीन भारत का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा विवादों के बावजूद व्यापारिक संबंध व्यापक हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए केवल बाहरी घटना नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन का विषय है। भारत और चीन की तुलना करें तो चीन ने पिछले तीन दशकों में विनिर्माण, निर्यात, आधारभूत संरचना और तकनीकी उत्पादन के माध्यम से स्वयं को वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित किया। चीन की आर्थिक नीति केंद्रीकृत और तीव्र निर्णय क्षमता वाली रही है। इसके विपरीत भारत का विकास लोकतांत्रिक व्यवस्था, विविधता और संस्थागत संतुलन पर आधारित रहा है। भारत की शक्ति उसकी युवा आबादी, लोकतंत्र, सेवा क्षेत्र और डिजिटल क्षमता में निहित है, जबकि चीन की शक्ति विनिर्माण, निर्यात और पूंजी निवेश में रही है। अमेरिका के साथ चीन के संबंधों में सुधार होने की स्थिति में भारत के सामने यह चुनौती होगी कि वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक उपयोगिता को और अधिक प्रभावशाली बनाए।

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर चाइना प्लस वन रणनीति में निहित है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले वर्षों में चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में प्रयास किए हैं। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत, वियतनाम और अन्य देशों की ओर बढ़ी हैं। भारत यदि अपनी औद्योगिक नीतियों, आधारभूत संरचना, श्रम सुधार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करता है तो वह वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। किंतु यदि भारत आवश्यक गति से सुधार नहीं कर पाया तो यह अवसर अन्य देशों के पास चला जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में भी अमेरिका-चीन संबंधों का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और रेयर अर्थ मिनरल्स नई शक्ति राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। अमेरिका तकनीकी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है जबकि चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत इन दोनों के बीच एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। भारत के पास प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा को वैश्विक नेतृत्व में बदलने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि चाहिए।

भू-राजनीतिक दृष्टि से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संकटों पर अमेरिका और चीन की भूमिका निर्णायक है। यदि दोनों देशों के बीच समझ बढ़ती है तो सैन्य टकरावों की आशंका कम हो सकती है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर होंगे और तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह अत्यंत लाभकारी स्थिति होगी। लेकिन यदि दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव विस्तार के लिए संकटों का उपयोग करती हैं तो विश्व अस्थिरता और बढ़ सकती है। भारत की विदेश नीति के लिए यह समय अत्यंत निर्णायक है। भारत को अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए चीन के साथ व्यावहारिक संबंधों का संतुलन बनाना होगा। साथ ही उसे वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत करनी होगी। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की अवधारणा प्रस्तुत की थी, वह भविष्य की विश्व व्यवस्था का वैकल्पिक मॉडल बन सकती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अमेरिका और चीन जहाँ शक्ति संतुलन की राजनीति में उलझे हुए हैं, वहीं भारत सहअस्तित्व, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग की नीति पर चल रहा है। अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा शक्ति प्रदर्शन पर आधारित है जबकि भारत का दृष्टिकोण विकास, मानवीय मूल्यों और वैश्विक साझेदारी पर केंद्रित रहा है। यही भारत की विशिष्टता और शक्ति है।

आज दुनिया में यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि क्या अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया को पुनः अपने प्रभाव क्षेत्र में बाँटने का प्रयास करेंगे? क्या छोटे देशों की भूमिका सीमित हो जाएगी? क्या फिर वही स्थिति बनेगी जब महाशक्तियाँ विश्व राजनीति को अपनी उँगलियों पर नचाती थीं? इन प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आज की दुनिया शीत युद्ध काल की दुनिया नहीं है। भारत, जापान, यूरोपीय संघ, ब्राजील, आसियान और अफ्रीकी देशों का बढ़ता प्रभाव विश्व व्यवस्था को बहुध्रुवीय बनाए रखने में सक्षम है। भारत को इस बदलती परिस्थिति में अपने संकल्पों को सुदृढ़ करना होगा, विकास के नए मानक गढ़ने होंगे और अपनी रणनीतिक क्षमता को विस्तार देना होगा। क्योंकि बदलती दुनिया में प्रश्न यह नहीं है कि अमेरिका और चीन क्या करेंगे, बल्कि यह है कि भारत स्वयं को किस ऊँचाई पर स्थापित करेगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि स्त्री-प्रजनन की आभ्यन्तरिक बलियों को वैज्ञानिक नियमानुसार बाहर निकाल लिया जाय तो वह पु व्यंजन का सा आकार बन जायेगा, इसी प्रकार पुरुष चिन्ह को विधिवत् अन्दर वलित कर देने पर स्त्री चिन्ह बन जाएगा। कहना न होगा कि यह पंक्तियें सर्वसाधारण को चाहे होली का विनोद ही क्यों न जंचें, परन्तु वर्तमान विज्ञान इसे सम्भवता की सीमा में अवश्य परिगणित करता है।

अदि अघटितघटनापटीयसी प्रकृति देवी स्वयं ही शङ्कावादी महा-शय जी को अपटूडेट श्रीमती के रूप में परिवर्तन करना चाहे तब तो महाशय जी के पुरुषोचित श्रङ्ग श्रतीव मन्थरगति से स्त्रीत्व दशा में परिणत होने लगेंगे, अन्त में गर्भाशय और स्तन्याशय भी स्त्रियों के समान ही बन जाऐंगे। पाठकों के सन्तोषार्थ हम ऐसी एक दो ताजा घटनाओं का यहां उल्लेख करते हैं-

दो लड़कियों का बाप औरत हो गया -

आर्यसमाजी पत्र उर्दू प्रताप के गुरुदासपुर के सम्वाददाता ने लिखा है कि तीन साल का शर्मा गुजरा कि भागलपुर जिला कटक में हरिकृष्ण नामक आदमी (जिसके दो लड़कियाँ भी पैदा हो चुकी थी) जब 35 वर्ष का हुआ तो उसके पुंस्त्व के चिन्ह मिटने लगे और वह कई मास में स्त्री हो गया तो उसका नाम हरिदेवी रखखा गया और इसकी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर के पास गई तो उन्होंने कहा योरोप में ऐसी कई घटनाएं हो गुजरी हैं।

[जुलाई सन् 1625 के धीमान ब्राह्मण (मुजफ्फरनगर) से-] इसी तरह की एक घटना टर्की में हुई थी। वहां स्त्री पुरुष वन गई थी जिसके साथ वहाँ के राज घराने तक की कन्यायें भी विवाह करने के लिये लालायित थीं। क्या अब भी शङ्कावादी इस कथा पर भाक्षेप करने का साहस करेगा?

क्रमशः ...

विश्व मधुमक्खी दिवस

सुनील कुमार महला

प्रतिवर्ष 20 मई को संयुक्त राष्ट्र(यूएन) द्वारा घोषित विश्व मधुमक्खी दिवस (वर्ल्ड बी डे) मनाया जाता है। वास्तव में इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति आम लोगों को जागरूक करना तथा उनके संरक्षण की दिशा में वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां केवल और केवल शहद बनाने वाली छोटी सी जीव मात्र ही नहीं हैं, बल्कि वे इस पृथ्वी पर जीवन, खाद्य सुरक्षा, जैव- विविधता और पारिस्थितिक संतुलन की अत्यंत महत्वपूर्ण व अहम् कड़ी हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि यदि मधुमक्खियों का अस्तित्व संकट में पड़ता है, तो मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण

भी गंभीर संकट में आ जाएंगे। इसलिए मधुमक्खियों का संरक्षण केवल और केवल पर्यावरणीय आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि उनका जीवन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं मानव अस्तित्व की भी अहम् आवश्यकता है। अतः हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने, धरती से रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने, जैविक खाद का अधिक उपयोग करने, जैविक खेती अपनाने तथा प्राकृतिक जैव-विविधता को बचाने की दिशा में अपने सामूहिक व यथेष्ठ प्रयास करने होंगे। पाठक जानते होंगे कि खेती, जैव-विविधता और खाद्य सुरक्षा में मधुमक्खियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में, इस दिवस को मनाने के प्रमुख उद्देश्यों में मधुमक्खियों और अन्य परागणकर्ताओं के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जैव-विविधता और खाद्य-सुरक्षा की रक्षा करना, मधुमक्खियों पर मंडरा रहे खतरों जैसे कि खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश की ओर ध्यान आकर्षित करना, सतत कृषि और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में मधुमक्खी पालन के योगदान को रेखांकित करना आदि शामिल है। हाल फिलहाल, यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इस दिवस की थीम-प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां, हम सभी का पोषण करती हैं रखी गई थी, जबकि इस वर्ष 2026 की थीम-लोगों और पृथ्वी के लिए मधुमक्खियों के साथ मिलकर कार्य करें निर्धारित की गई है।

बहरहाल,यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें, तो इसकी शुरुआत का प्रस्ताव सर्वप्रथम यूरोपीय देश स्लोवेनिया ने रखा था। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया तथा पहली बार यह दिवस वर्ष 2018 में मनाया गया। 20 मई की तिथि इसलिए चुनी गई, क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जान्सा का जन्म हुआ था। मधुमक्खियों के महत्व की यदि हम बात करें तो ये नीले ग्रह (पृथ्वी) के पारिस्थितिक संतुलन की प्रमुख आधारशिला मानी जाती हैं।

भारतीय राजनीति की सात जुगलबंदियां

रामचंद्र गुहा

बंगलूरू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मैं छह अगस्त, 2019 को अपने कुछ सहकर्मियों के साथ कॉफी पी रहा था। हम एक दिन पहले कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक युवा कंप्यूटर वैज्ञानिक ने टिप्पणी की—अब हमारे सामने मोदी 2.0 नहीं, बल्कि शाह 1.0 है। यह टिप्पणी इसलिए आई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने ही भारत के एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने की योजना बनाई और उसे लागू किया। शायद इसे पूरी तरह शाह 1.0 कहना अतिशयोक्ति हो, लेकिन अब इसमें संदेह नहीं है कि अमित शाह सरकार में प्रधानमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वही ऐसे मंत्री हैं, जिनके पास वास्तविक अधिकार और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है।

मोदी-शाह की यह राजनीतिक जुगलबंदी भारतीय राजनीति में पहली नहीं है। आजाद भारत के शुरुआती वर्षों में जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाई पटेल की साझेदारी इसका एक बड़ा उदाहरण थी। आज की राजनीति उन्हें प्रतिद्वंद्वी और विरोधी के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तव में वे मित्र, सहयोगी और सहकर्मी थे।

विभाजन की त्रासदी, अभाव, संघर्ष और सामाजिक विभाजन के बीच यदि एक संयुक्त और लोकतांत्रिक भारत का निर्माण संभव हो पाया, तो उसका बड़ा कारण नेहरू और पटेल की जुगलबंदी है। पटेल ने भारत को भौगोलिक रूप से एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई-उन्होंने रियासतों का विलय कराया, प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाया, हिंदू दक्षिणपंथ और कम्युनिस्ट वामपंथ के उग्र तत्वों को नियंत्रित किया, साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन करने का माहौल बनाया, जिसका नेतृत्व डॉ. भीमराव आंबेडकर कर रहे थे।

दूसरी ओर, नेहरू ने भारत को भावनात्मक रूप से एकजुट करने का कार्य किया। उन्होंने धार्मिक

और भाषायी अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के समान अधिकारों की वकालत की और भारी अभिजात्य विरोध के बावजूद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का दृढ़ समर्थन किया।

निश्चित रूप से नेहरू और पटेल के बीच मतभेद भी थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए उन मतभेदों को पीछे छोड़ दिया। यह भी सच है कि उन्हें आंबेडकर जैसे प्रतिभाशाली मंत्रियों और सक्षम नौकरशाहों का सहयोग मिला। फिर भी इतिहासकारों ने प्रमाण सहित दिखाया है कि बिखरे हुए भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने में उनकी साझेदारी की निर्णायक भूमिका थी।

दिसंबर, 1950 में पटेल की मृत्यु और अगले साल आंबेडकर के इस्तीफे के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली नेता बन गए, जो शायद पूरी तरह लाभदायक नहीं था। भारतीय राजनीति में अगली बड़ी 'जोड़ी' 1960 के दशक के आखिर में उभरी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्व राजनयिक पीएन हक्सर को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया।

हक्सर जल्द ही इंदिरा गांधी के मंत्रियों से अधिक प्रभावशाली बन गए। 1970 से 1975 के बीच वे उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी और प्रमुख सलाहकार रहे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जैसी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता की योजना बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही कृषि और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने में भी उनका योगदान रहा।लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी था। इंदिरा गांधी की केंद्रीकरण और सरकारी नियंत्रण पर आधारित आर्थिक नीतियों को तैयार करने में भी हक्सर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने आगे चलकर देश को नुकसान पहुंचाया।

1975 में पीएन हक्सर को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने ले ली। इंदिरा गांधी और संजय गांधी की यह साझेदारी देश को निरंकुशता की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार थी। नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन, प्रेस पर सेंसरशिप, न्यायपालिका को नियंत्रण में करना, नौकरशाही और पुलिस को मां-बेटे के अधीन बना देना तथा सभी राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालना-ये सब उसी दौर की विशेषताएं थीं और इंदिरा गांधी-हक्सर की साझेदारी के विपरीत, इस गठजोड़ में कोई सकारात्मक पक्ष नहीं था।

इसके बाद सरकार में जो अगली महत्वपूर्ण साझेदारी उभरी, वह थी पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की। 1991 से 1996 के बीच प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में दोनों ने मिलकर देश को लाइसेंस-परमिट-कोटा राज से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने तीन दशकों तक स्थिर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे गरीबी में कमी आई, एक बड़े मध्यम वर्ग का उदय हुआ और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी।

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेई और आड़वाणी की साझेदारी सामने आई। 1980 और 1990 के दशकों में दोनों ने मिलकर भाजपा को कांग्रेस के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में खड़ा किया। 1998 से 2004 के बीच जब भाजपा सत्ता में रही, तब वाजपेयी प्रधानमंत्री और आडवाणी गृह मंत्री थे। उन्होंने राव और मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण के रास्ते को आगे बढ़ाया, जिसमें यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे योग्य मंत्रियों का भी योगदान रहा।

क्योंकि उनकी सरकार कई दलों के गठबंधन पर आधारित थी, इसलिए संघ परिवार की बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों को पूरी तरह खुलकर काम करने का अवसर नहीं मिला। 2004 में भाजपा अप्रत्याशित रूप से सत्ता से बाहर हो गई। अगले दस वर्षों तक देश पर कांग्रेस-प्रधान बहुदलीय गठबंधन ने शासन किया। एक बार फिर दो व्यक्तियों के हाथ में सबसे अधिक शक्ति थी-प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति प्रभावशाली बनी रही, वहीं सोनिया गांधी और उनकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मार्गदर्शन में गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र खड़ा करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, लेकिन इस साझेदारी की उपलब्धियां इस वजह से फीकी पड़ गईं कि सत्ता की चाबी किसके पास है। शक्ति होनी प्रधानमंत्री के पास चाहिए थी, लेकिन स्वभाव से संकोची और जोखिम से बचने वाले मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी को उन विषयों में भी अत्यधिक हस्तक्षेप करने दिया, जो केवल उनके अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए थे, जैसे शिक्षा नीति।

मोदी-शाह की जुगलबंदी में आर्थिक प्रगति धीमी हुई है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता की भारतीय परंपरा पर लगातार हमले भी उनके कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन इस लेख में जिन सात जुगलबंदियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें अंक देने या क्रमबद्ध करने से बचना चाहता हूं। फिर भी नेहरू और पटेल की जोड़ी को श्रेष्ठ और रचनात्मक मानता हूं। मैं इंदिरा गांधी-संजय गांधी और नरेंद्र मोदी-अमित शाह की जोड़ी को देश हित में नहीं देखता हूं।

आज का इतिहास

1902 क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका से आजादी मिली।
1902 टॉमस एस्ट्राडा पाल्मा देश के पहले राष्ट्रपति बने।
1919 स्वतंत्रता का तुर्की युद्ध 19 मई, 1919 को तुर्की राष्ट्रवादियों और मित्र राष्ट्रों ग्रीस, आर्मेनिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच तीन अलग-अलग मोर्चों अर्थात् पश्चिमी मोर्चे, पूर्वी मोर्चे और दक्षिणी मोर्चे पर हुआ। मुस्तफा केमल अतातुर्क ने तुर्की आंदोलन का नेतृत्व किया और मित्र राष्ट्रों की सेना को हराया।
1923 स्टेनली बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने।
1926 रेलवे श्रम अधिनियम पारित किया गया।
1927 बोइंग 40 ए कंपनी द्वारा निर्मित पहला यात्री एयरलाइन पहली बार उड़ाया गया।
1927 सऊदी अरब को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली।
1930 दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा 19 मई, 1930 को महिला उत्थान अधिनियम, 1930 पारित किया गया था, जिसमें केवल 21 वर्ष से अधिक आयु की श्वेत महिलाओं को ही मतदान का अधिकार दिया गया था।
1956 हाइड्रोजन बम का पहला संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई परीक्षण 20 मई, 1956 को प्रशांत महासागर के बिकनी एटोल में किया गया था।
1964 अमेरिकी भौतिकविदों रॉबर्ट वुड्रो विल्सन और अर्नो पेनज़ियास ने 20 मई, 1964 को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की। दोनों ने इस खोज के लिए भौतिकी में 1978 का नोबेल पुरस्कार अर्जित किया, जो बहुत महत्व का है क्योंकि कॉस्मिक माइक्रोवेव बिग बैंग से खत्म थर्मल विकिरण है इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है।
1965 पाकिस्तान का बोइंग 720-बी विमान मिस्र के काहिरा में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 121 लोगों की मौत हुई।
1969 हैम्बर्गर हिल की लड़ाई 20 मई, 1969 को समाप्त हुई, उत्तर वियतनामी बलों के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण वियतनामी के बीच लड़ाई हुई। उत्तर वियतनामी सेना पर सामरिक जीत हासिल करने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दक्षिण वियतनाम से वापसी की घोषणा की।
1983 फ्रांसीसी virologist Luc Montagnierpp की अगुवाई में शोधकर्ताओं की एक टीम ने एचआईवी की उनकी खोज को पुनः प्रकाशित किया, हालाँकि उन्हें अभी तक यह पता नहीं था कि यह एड्स है या नहीं।
1990 रोमानियाई प्रथम पोस्ट-कम्युनिस्ट राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव 20 मई, 1990 को हुए थे। इयोन इलिससु ने 90त्न मतों से चुनाव जीता और रोमानिया के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

मुख्यमंत्री 'सतीशन' के सामने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती

कल्याणी शंकर

कांग्रेस पार्टी को केरल के मुख्यमंत्री का चयन करते समय महत्वपूर्ण आंतरिक गुटीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह प्रक्रिया 11 दिनों तक चली और इसका उद्देश्य विभिन्न पार्टी समूहों के बीच विवादों को सुलझाना था। इन तनावों से निपटना कठिन था और इस दौरान दिखाई गई सहनशीलता सराहनीय है। के.सी. वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद वी.डी. सतीशन को इस भूमिका के लिए चुना गया। प्रियंका और राहुल गांधी ने अपना निर्णय लेते समय जनभावनाओं पर विचार किया। चयन प्रक्रिया के दौरान आंतरिक तनाव उभरे लेकिन अंततः वेणुगोपाल ने पार्टी के व्यापक हित के लिए सतीशन की नियुक्ति का समर्थन किया।

कांग्रेस आलाकमान विभाजित था- सोनिया गांधी ने चेन्निथला का समर्थन किया, राहुल गांधी ने वेणुगोपाल का और प्रियंका गांधी ने सतीशन का पक्ष लिया। इस दरार ने पार्टी के आलाकमान के भीतर आंतरिक संघर्षों को उजागर किया। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस को अपने सहयोगी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम.एल.) और जनभावनाओं से दबाव का सामना करना पड़ा, जिसने गांधी परिवार की छवि को प्रभावित किया। राहुल और प्रियंका गांधी ने स्थिति पर चर्चा की लेकिन उनके मतभेद कांग्रेस कार्यालयों के बाहर और प्रियंका के वायनाड कार्यालय में प्रदर्शित पोस्टरों में स्पष्ट थे। ऐसा ही एक पोस्टर था, 'श्रीमान राहुल, के.सी. आपके थैला ढोने वाले हो सकते हैं लेकिन केरल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी', जो वेणुगोपाल के प्रति राहुल की पसंद पर असंतोष व्यक्त कर रहा था। राहुल गांधी ने जनभावनाओं का आकलन करके और दावेदारों वेणुगोपाल, सतीशन और चेन्निथला के साथ समन्वय करके केरल के मुख्यमंत्री का चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यूनाइटेड डैमोक्रेटिक फ्रंट (यू.डी.एफ.) के भीतर चुनाव के बाद के गतिरोध को दूर करने के लिए दिल्ली में मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी के साथ व्यापक बैठकें कीं।

आई.यू.एम.एल. ने वी.डी. सतीशन के धर्मनिरपेक्ष रुख के लिए उनका समर्थन किया। वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में सतीशन की नियुक्ति के लिए अपना समर्थन व्यक्त करने हेतु राहुल और प्रियंका के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक मुलाकात की। हालांकि वेणुगोपाल भी एक प्रमुख उम्मीदवार थे, उन्होंने जोर दिया कि पार्टी के हितों को सबसे पहले आना चाहिए। सतीशन, जो 6 बार के विधायक और

यू.डी.एफ. अभियान के नेता हैं, ने इस्तीफा देने का संकल्प लिया था यदि यू.डी.एफ. केरल की 140 सीटों में से कम से कम 100 सीटें हासिल नहीं कर पाता। गठबंधन ने अंततः 102 सीटें जीतीं, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो सतीशन के नेतृत्व में विश्वास को दर्शाती है।

वेणुगोपाल के लिए राहुल गांधी का समर्थन इस बात से जटिल हो गया कि वेणुगोपाल को विधायक बनने के लिए अपनी सांसद भूमिका से इस्तीफा देना पड़ता। जमीनी स्तर के विरोध प्रदर्शनों ने सतीशन का पक्ष लिया, जो पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी आवाज के रूप में उभरे। उन्होंने एक दशक के बाद केरल में यू.डी.एफ. की सत्ता में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री के रूप में वेणुगोपाल की संभावित नियुक्ति के खिलाफ इन जमीनी विरोध प्रदर्शनों ने कांग्रेस के भीतर आंतरिक विभाजन को उजागर किया। सतीशन ने स्वीकार किया कि इन प्रदर्शनों ने जनभावनाओं को प्रभावित किया। कांग्रेस पार्टी खुद को भाजपा के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में पेश करने का अवसर देख रही है। तमिलनाडु में, कांग्रेस ने द्रमुक के साथ अपने लंबे गठबंधन को समाप्त कर दिया है और अब विजय की तमिलनाडु वेत्री कडग़म (टी.वी.के.) के साथ सहयोग कर रही है, जिससे पार्टी के नेताओं को क्षेत्रीय भागीदारों के साथ जटिल संबंधों को बनाए रखते हुए स्वतंत्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिल रही है।

केरल के राजनीतिक परिदृश्य को नियंत्रित करने की सतीशन की क्षमता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगी। हालांकि वह पार्टी के साथ सरेखित होंगे लेकिन स्पष्ट शक्ति गतिशीलता और पदानुक्रम काम कर रहे हैं। ईसाई और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन ने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर दिया, जिससे कई लोग इससे दूर हो गए और पिनाराई विजयन के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में योगदान दिया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में, वी.डी. सतीशन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पार्टी की एकता बनाए रखना, आई.यू.एम.एल. जैसे मुखर सहयोगियों के साथ गठबंधन का प्रबंधन करना और संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना शामिल हैं। उनकी तत्काल चुनौती मंत्रिमंडल का गठन है, जिसमें कांग्रेस के भीतर विभिन्न गुटों को समायोजित करना, आई.यू.एम.एल. जैसे प्रमुख गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना और पार्टी के भीतर नाराजगी को रोकना शामिल है।

उन्हें एक महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटे और राज्य पर ऋण का भी समाधान करना और आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाना होगा। उन्हें अपनी बयानबाजी में सुधार करने, अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति को नेविगेट करने, लीग और जमात-ए-इस्लामी के साथ संबंधों के बारे में भाजपा की आलोचना का मुकाबला करने और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक गुटों से तोडफ़ोड़ से बचते हुए एकता बनाए रखने की आवश्यकता है। जमात-ए-इस्लामी ने सतीशन के लिए मुस्लिम वोटों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे सहयोगियों से निपटते समय अपनी धर्मनिरपेक्ष साख बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

सतीशन अब एक विधायी दल का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें ऐसे सदस्य शामिल हैं जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया था। वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला सहित शक्तिशाली गुट जल्द ही अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सतीशन जमात के हितों और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी, सुन्नी सर्वोच्च निकाय 'समस्त', जिसने उन्हें निहित समर्थन प्रदान किया है, के हितों को संतुलित करने की कठिन चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि वह ड्क्षहदू मतदाताओं को अलग-थलग कर सकते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के बढ़ते प्रभाव के बारे में ड्क्षचतित हैं, साथ ही उदारवादी और सुधारवादी मुस्लिम आवाजों को भी, जो इन घटनाक्रमों के बारे में आशंकित हैं।

आखिर कितनी लंबी है भारत बांग्लादेश सीमा, कैसे होगा पूरा काम?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह दोनों ही बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही 45 दिनों में बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी पहली कैबिनेट के बैठक में पहला निर्णय इसी पर लिया। बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2,216.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बंगाल के कुल 9 जिले बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर 24 परगना। भारत-बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 4,096.7 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा भी है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बंगाल- 2,216.7 किलोमीटर, त्रिपुरा- 856 किलोमीटर, मेघालय- 443 किलोमीटर, मिजोरम- 318 किलोमीटर असम- 263 किलोमीटर। बंगाल बांग्लादेश के साथ 2,216.7 किलोमीटर में से करीब 569 किलोमीटर की असुरक्षित सीमा साझा करता है, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका सबसे बदनाम माना जाता है. यहां बाड़ न होने के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए आसानी से सीमा पार कर भारत आ जाते हैं। बिना फेंसिंग के बाकी बचे करीब 113 किलोमीटर सीमा एरिया ऐसा है, जहां नदी-तालाब की वजह से किसी भी सूरत में बाड़बंदी नहीं की जा सकती। भौगोलिक कारणों से कुछ क्षेत्रों में नदियों और रेतीले किनारों के कारण स्थायी कांटेदार बाड़ लगाना मुश्किल होता है, जिसके लिए सरकार फ्लोटिंग बीओपी और फ्लडलाइटिंग जैसे वैकल्पिक निगरानी उपायों का उपयोग करती है। इस सीमा की सुरक्षा और निगरानी का कार्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा ही किया जाता है। पूर्व राज्य सरकार द्वारा जमीन ना मिलने से यहां फेंसिंग नहीं हो पा रही थी। इस वजह से घुसपैठ भी बढ़ रही थी। आंकड़ों पर गौर करें तो 2023 में 1547 और 2024 में 1694 घुसपैठिए बांग्लादेश से लगते बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। इनमें 2025 में और बढ़ोतरी हुई। इनमें मवेशियों और ड्रग्स की भी तस्करी हो रही थी। नकली नोटों (जाली करेंसी), हथियारों और नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है. सीमा पार के अपराधी भारतीय किसानों के खेतों से पकी हुई फसलें और मवेशी चुरा ले जाते हैं. घुसपैठियों की तो पौ बारह थी जो कि पूर्व सरकार के फिक्स्ड वोटबैंक थे। जमीन अब मिलने से इस पूरे इलाके में जल्द बाड़बंदी की जा सकेगी। जिसके बाद इस तरह की अवैध घुसपैठ बंद हो जाएगी। हालांकि, ऐसा नहीं है कि इस बिना बाड़बंदी वाले एरिया में बीएसएफ की निगरानी नहीं है। लेकिन फेंसिंग होने के बाद यह प्रॉपर हो सकेगी, जिसमें कहीं से भी घुसपैठ होने की आशंका बेहद कम हो जाएगी। दरअसल, घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी समस्या बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर ही आ रही थी। जहां 2216.7 किलोमीटर सीमा में से 1647.7 किलोमीटर सीमा एरिया में तो कंटीले तार वाली बाड़ लगा दी गई थी लेकिन बाकी बचे 569 किलोमीटर सीमा इलाके में बाड़ नहीं लग पाया। घुसपैठ के अधिकतर प्रयास इन्हीं बिना फेंसिंग वाले खुले सीमा क्षेत्र से होते हैं।

तमिल सत्ता राजनीति में हिंदी के पक्ष में उठी आवाज

उमेश चतुर्वेदी

भाषाएं संचार का साधन तो होती हैं, इस प्रक्रिया में वे दिलों को भी जोड़ती हैं। लेकिन जब भाषाओं को राजनीतिक औजार बनाया जाता है, तब संचार का जरिया होने के बावजूद वे दिलों में दरार पैदा करने का माध्यम भी बन जाती है। तमिलनाडु में हिंदी की यही स्थिति रही है। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने हिंदी में देश को जोड़ने की क्षमता देखी थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी राजा जी ने तीस वर्षों तक दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का कामकाज संभाला।

तमिल माटी का वह सपूत तमिल लोगों की जुबान पर हिंदी को बसाना चाहता था, ताकि आजाद भारत में उत्तर और दक्षिण के दिलों को सीधे जोड़ा जा सके। तमिलनाडु की नवेली सत्ता की युवा मंत्री एस कीर्तना को राजा जी की ही कड़ी में रखा जा सकता है। तमिल राजनीति में वह राजा जी के बाद दूसरा चेहरा हैं, जो न सिर्फ फर्राटेदार हिंदी बोलती हैं, बल्कि हिंदी के जरिये देश से जुड़ने की बात करती हैं।

दस मई को विजय मंत्रिमंडल की सबसे युवा मंत्री बनने के बाद एस कीर्तना ट्रोलरों के निशाने पर रहीं। उनका हिंदी बोलना तमिल राजनीति के लिए हैरत और गुस्से की वजह बन गया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने हिंदी में बात की थी। तमिल राजनीति का परंपरावादी धड़ा यह कैसे बर्दाश्त करता कि उनकी मंत्री हिंदी बोले। लेकिन उसका भी उन्होंने जवाब दिया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'मैं हिंदी में बात कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी का प्रतिनिधित्व पूरे भारत में और दूसरे देशों तक पहुंचे। इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूं। हर किसी को मेरे नेता के बारे में पता होना चाहिए। हर किसी को मेरी पार्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए।'

तमिलनाडु की राजनीति के लिए भाषा का मुद्दा 1938 में ही संवेदनशील बन गया था, जब तत्कालीन मद्रास प्रांत की सरकार के मुखिया के नाते राजा जी ने प्राथमिक शिक्षा

में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत की। तब डीएमके के संस्थापक सीए अन्नादुरै ने हिंदी विरोध में मोर्चा खोला, जिससे राजा जी को हिंदी पढ़ाने के कदम से पीछे हटना पड़ा। इसके बावजूद 1968 तक वह हिंदी के कट्टर समर्थक बने रहे। डीएमके का गठन भले 1949 में हुआ, पर जिन मुद्दों को लेकर 1944 में उसकी पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी बनी थी, उसमें एक मुद्दा तमिल अस्मिता से भी जुड़ा था।

तमिल अस्मिता की जब भी बात होती है, वह घूमकर हिंदी विरोध पर चली जाती है। द्रविड़ दलों के राजनीतिक उभार के पीछे का एक मुद्दा यह भी रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत जब 26 जनवरी, 1965 को हिंदी को पूरे देश की राजभाषा के रूप में स्थापित होना था, तब तीखा विरोध तमिलनाडु में ही शुरू हुआ था, जो कुछ साल बाद हिंसक भी हो गया। तभी से तमिल राजनीति में हिंदी विरोध की घोषित परंपरा जारी है।

यह अलग बात है कि सूचना और संचार क्रांति की वजह से एक ऐसी नयी पीढ़ी तैयार हुई है, जिसे हिंदी विरोध के सियासी हथियार में कोई दिलचस्पी नहीं है। तमिलनाडु में विजय सरकार की सबसे युवा मंत्री एस कीर्तना इसी पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं। पटाखा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध शिवकाशी से विधायक कीर्तना की उम्र तीस साल भी नहीं है। वह बदले दौर की नेता हैं, जिन्हें भाषा राजनीति का औजार नहीं, संचार का साधन नजर आती है। राजनीति की एक रवायत है।

वह लीक पर चलने में ज्यादा विश्वास करती है। ऐसे में कीर्तना का हिंदी बोलना एक तरह से लीक को तोड़ना है। अगर लीक तोड़ने के लिए उनकी ट्रोलिंग नहीं होती, तो हैरत होती। हिंदी के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया गया। तमिल राजनीति में सी राजगोपालाचारी के बाद कीर्तना संभवतः दूसरी राजनेता हैं, जो न सिर्फ धाराप्रवाह हिंदी बोलती हैं, बल्कि हिंदी के समर्थन में तर्क भी देती हैं।

विजय की राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकीं कीर्तना जानती हैं कि हिंदी के बिना अपनी बात दूर-दूर तक नहीं पहुंचाई जा सकती। कीर्तना हिंदी को 'राष्ट्रीय जुड़ाव' का माध्यम मानती हैं और कहती हैं, कि तमिल सीमाओं से बाहर पार्टी और विजय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हिंदी जरूरी है। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल होकर हिंदी से दूर रही पीढ़ी अब बुजुर्ग हो गयी है। उसमें कई लोग ऐसे हैं, जिन्हें हिंदी न सीखने का मलाल है।

धीरे-धीरे ही सही, तमिलनाडु की नयी पीढ़ी हिंदी के प्रति सहज हो रही है। खुद कीर्तना की पार्टी तमिल गौरव को बनाये रखते हुए राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कीर्तना की यह सोच तमिलनाडु की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिंदी के जरिये गैर तमिल क्षेत्रों के लोगों से अपने विचार साझा करना चाहती है। अब तक भाषा का मुद्दा तमिलनाडु में तमिल अस्मिता और गौरव से जुड़ा रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय मुद्दों पर तमिल राजनीति की सोच से देश वंचित रह जाता है।

कीर्तना की सोच इसी सोच को चुनौती है। चूंकि वह परिचित और परीक्षित राजनीतिक लीक से अलग है, इसलिए इसका विरोध स्वाभाविक है। लेकिन यह तमिल राजनीति की नयी पीढ़ी की बदलती सोच का भी प्रतीक है। भाषा के मुद्दे पर बदलाव रातोंरात नहीं आता, वह धीरे-धीरे आता है। कीर्तना की सोच इसी धीमी बदलाव का जरिया है। भाषाओं के जरिये देश के दिलों को जोड़ने वालों को इसका स्वागत करना ही चाहिए।

बंगालियों की प्रताड़ना का पिछला हिसाब और अगली राजनीति

अकु श्रीवास्तव

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही कई ऐतिहासिक और सख्त प्रशासनिक घोषणाएं की हैं। यह राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देने की एक बड़ी कवायद है। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि राज्य के सभी थानों को पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई पुलिस ज्यादती और उत्पीडऩ की शिकायतों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। यानी वे सभी मामले जो 2021 से अब तक हैं और अभी तक पुलिस ने उन्हें दर्ज नहीं किया है। अब ऐसे लोग या भाजपा कार्यकर्त्ता, जिनके पास उत्पीडऩ की पुरानी शिकायतें हैं, वे अब थाने जाकर दर्ज करा सकते हैं।

ऐसी शिकायतों का मुख्य संबंध राजनीतिक हिंसा, अवैध वसूली, कट मनी और तोला बाजी और चुनावी गड़बडिय़ों से रहा है। हजारों मामले ऐसे बताए जाते हैं, जिनमें पीड़ितों ने डर या पुलिस की निष्क्रियता के कारण औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई या पुलिस ने उन्हें दर्ज करने से मना कर दिया। विपक्षी कार्यकर्त्ताओं (विशेषकर भाजपा) द्वारा अपने घरों से बेदखल किए जाने और संपत्ति में तोडफ़ोड़ की कई शिकायतें राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण थानों तक नहीं पहुंच पाईं। चुनाव बाद की हिंसा के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न और छेड़छाड़ के हजारों मामले सामने आए, जिनमें से कई सामाजिक कलंक और धमकियों के डर से पुलिस में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हो सके। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक जांच समिति बनी थी। समिति ने पाया था कि बहुत सी शिकायतें थानों में नहीं ली गईं और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी।

शुभेंदु अधिकारी ने 4 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया, जिनके तहत पीड़ित लोग अब थानों में अपनी नई शिकायतें या प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं, जिनमें राजनीतिक हिंसा, पुलिस बर्बरता, महिला उत्पीडऩ, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी की बैठक राजनीतिक रूप से भी बेहद प्रतीकात्मक रही, क्योंकि इसका आयोजन डायमंड

हार्बर में किया गया था, जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टी.एम.सी. महासचिव अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। यानी सबसे ज्यादा मामले यहीं के हो सकते हैं और शिकायतें तो बहुत ही होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रणनीति आक्रामक और कानूनी कार्रवाई पर केंद्रित है।

चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी के स्वामित्व वाली कंपनी 'लीप्स एंड बाउंड्स' की 24 संपत्तियों की सूची का खुलासा किया है और उनकी जांच की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल में गठित पुलिस वैल्फेयर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि यह बोर्ड अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया था और एक राजनीतिक संगठन की तरह काम कर रहा था।

मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, उन्होंने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और जनगणना कार्य को तुरंत लागू करने की मंजूरी दी। साथ ही, केंद्र की सहायता वाली अन्य योजनाओं को भी राज्य में हरी झंडी दे दी गई है। राज्य में अवैध वसूली सिंडिकेट और टोल नाकों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों या फेरीवालों से कोई भी अवैध वसूली नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसा होने पर लोग सीधे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

प. बंगाल में सबसे बड़ी समस्या सरकारी योजनाओं का लाभ देने, आवास आबंटन या सरकारी नौकरियों के नाम पर तृणमूल कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय नेताओं द्वारा अवैध रूप से 'कटमनी' वसूली की रही है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति पर स्थानीय नेताओं और सिंडिकेट का कब्जा होता था, जो जबरन अपनी दरों पर घटिया सामग्री बेचकर वसूली करते थे। स्थानीय क्लबों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को डरा-धमका कर हर महीने अवैध हफ्ता वसूली आम बात थी। सड़कों और निर्माण क्षेत्रों में अवैध रूप से ड्रॉप गेट या बैरिकेड लगाकर अवैध टोल टैक्स वसूला जाता था।

अब तय है कि आम आदमी की उम्मीद यह रहेगी कि इस तरह की गतिविधियों पर अब पूरी तरह से लगाम लग जाए। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता जिस तरह स्थानीय गुंडों पर पार्टी के बड़े नेताओं की शह पर यह सब होने के आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि पहले जो ऐसे लोग कभी वामपंथी शासन में शह पा रहे थे, वही लोग टी.एम.सी. में आ गए। खतरा यही है कि आवरण बदलकर ये कहीं भाजपा में न आ जाएं। शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष में थे तो अक्सर टी.एम.सी. के नेताओं पर संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी भाजपा ने उठाया था। राज्य में साल 2016 में स्कूल सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और घोटाले के आरोप लगे थे। करीब एक साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। ऐसे में अब भाजपा की सरकार आने के बाद एक स्वच्छ सरकार देना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। खासतौर से तब, जब भाजपा के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं।

इस सबके बावजूद कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी को और बंगाल में नई-नई सत्ता में आई भाजपा सरकार को उन सब गलतियों से बचना होगा। अपराध से निपटने के लिए उन्होंने योगी मॉडल की शुरुआत तो कर ही दी है। पार्टी कार्यकर्त्ता तृणमूल या माकपा कार्यकर्त्ताओं के ढर्रे पर न चलने पाएं, यह देखना सबसे जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल के भद्र नागरिकों की शिकायतों पर अगर ईमानदारी से काम हुआ तो इसके नतीजे स्थाई और कारगर होंगे।

प्रधानमंत्री की पांच देशों की विदेश यात्रा के निहितार्थ

कमलेश पांडे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के हालिया विदेश दौरे के कई बड़े कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि मई 2026 में उनका यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया ऊर्जा संकट, ईरान युद्ध, सप्लाई चेन अस्थिरता और नए वैश्विक ध्रुवीकरण से गुजर रही है। लिहाजा, पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।

पहला, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक देश है। ईरान संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यूएई दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। लिहाजा भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी सप्लाई, ऊर्जा निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे अहम समझौते हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत भविष्य के किसी बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए खुद को सुरक्षित करना चाहता है।

दूसरा, पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ बढ़ रही है, क्योंकि यूएई ने पीएम मोदी का असाधारण स्वागत किया- एफ-16 एस्कॉर्ट और राष्ट्रपति स्तर की अगवानी- यह दिखाता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। इसके मायने ये निकलते हैं कि पाकिस्तान की पारंपरिक खाड़ी पकड़ कमजोर होगी और भारत की अरब देशों में स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। इससे रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार भी होगा।

तीसरा, यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारी विकसित होगी, क्योंकि नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का चयन बहुत रणनीतिक माना जा रहा है। चूंकि इन देशों से भारत सेमीकंडक्टर तकनीक, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई और रक्षा तकनीक और आर्कटिक एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहता है। विशेषकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए इस पहल के अपने रणनीतिक मायने हैं। चौथा, चीन और अमेरिका दोनों को संतुलित संदेश देने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा मल्टी-अलाइनमेंट नीति का हिस्सा भी है, इससे अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से संबंध, अरब देशों से सामरिक निकटता, यूरोप के साथ तकनीकी सहयोग, चीन के प्रभाव का संतुलन बढ़ेगा। चूंकि भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है।

पांचवां, भारत को निवेश हब बनाने की कोशिश यूएई द्वारा भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है। यह मेक इन इंडिया और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति से जुड़ा है।

छठा, घरेलू राजनीति के संकेत के नजरिए से दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से ईंधन बचाने, विदेशी यात्राएं कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद बड़े वैश्विक दौरे कर रहे हैं। इसका राजनीतिक संदेश यह जाएगा कि कठिन वैश्विक समय में सक्रिय नेतृत्व पीएम दे रहे हैं और भारत संकट में भी वैश्विक केंद्र बना हुआ है। इससे पीएम मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि मजबूत होकर चमकेगी। सातवां, भारत की वैश्विक छवि निर्माण के दृष्टिकोण से यह दौरा यह दिखाने का प्रयास भी है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा, तकनीक, व्यापार और सुरक्षा में निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। विशेषकर जी20 के बाद भारत अपनी विश्व नेतृत्व छवि को स्थायी बनाना चाहता है। इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभाव भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे जहां ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना रहेगी। साथ ही रक्षा-तकनीकी सहयोग विस्तार से वैश्विक प्रभाव में वृद्धि होगी। भारत की यह नई चाल चीन के लिए यूरोप और खाड़ी में भारत की सक्रियता चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। जबकि पाकिस्तान के लिए खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता रणनीतिक दबाव बढ़ा सकती है। वहीं, यूरोप के लिए चीन के विकल्प के रूप में भारत की अहमियत बढ़ेगी। जबकि अमेरिका के लिए भारत एक आवश्यक रणनीतिक साझेदार बना रहेगा, भले ही वह पूरी तरह अमेरिकी धड़े में न जाए। निष्कर्ष यह निकलता है कि पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।

अधिकमास की 'वरदा चतुर्थी' आज

अधिकमास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वरदा चतुर्थी कहा जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित होती है। धार्मिक ग्रंथ भविष्य पुराण के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि अधिकमास की वरदा विनायक चतुर्थी इस वर्ष 19 मई 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 19 मई को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाएगा।

वैदिक पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ अधिक मास की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 18 मिनट पर होगी और इसका समापन 20 मई को सुबह 11 बजकर 06 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, यह व्रत 20 मई को रखा जाएगा।

वरदा चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त

वरदा चतुर्थी पर रवि योग बन रहा है। यह योग 05:28 ए एम से 06:11 ए एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

वरदा चतुर्थी का धार्मिक महत्व

अधिकमास को सनातन धर्म में भगवान विष्णु और भक्ति-उपासना का विशेष महीना माना गया है। ऐसे में अधिकमास में आने वाली वरदा विनायक चतुर्थी का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से बुद्धि, धन, सफलता और संतान सुख की प्राप्ति होती है।वहीं आपको बता दें कि "वरदा" का अर्थ होता है वरदान देने वाले, इसलिए इस चतुर्थी पर गणपति भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

इस दिन व्रत रखने और गणेश मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तथा घर में सुख-शांति बनी रहती है। खासतौर पर नए कार्यों की शुरुआत, करियर, व्यापार और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यह दिन बेहद शुभ माना जाता है।

जेठ महीने में होंगे 59 दिन सूर्य–चंद्रमा की चाल से बढ़ता है एक महीना

हिंदू समेत कई धर्मों में होता है अधिक मास

हिंदू पंचांग में 2026 में जेठ का महीना 30 के बजाय 59 दिनों का है। क्योंकि इस बार एक एक्स्ट्रा महीना इसमें जुड़ा है। जिसे अधिक मास कहते हैं। एक्स्ट्रा महीना जुड़ने के बावजूद कैलेंडर गड़बड़ नहीं होगा।

ये हिंदी कैलेंडर का गणित है, इसलिए हर ढाई साल बाद ऐसा होता है। अब सवाल है कि ये होता कैसे है और ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, अधिक मास किसे कहते हैं ? इन सब सवालों के जवाब जानते हैं।

पहले ये जान लीजिए- हिंदी कैलेंडर का जेठ महीना 2 मई से शुरू होकर 29 जून को खत्म होगा। इसी बीच 30 दिन का अधिक मास भी रहेगा, जो कि 17 मई से 15 जून तक होगा। इस तरह जेठ महीना 59 दिनों का रहेगा।

अब समझते हैं अधिक मास का गणित

खगोलीय कालगणना: सूर्य-चंद्रमा की घड़ी में तालमेल बनाता है अधिक मास

अधिक मास का सबसे खास खगोलीय पक्ष यह है कि यह सूर्य और चंद्रमा की दो अलग-अलग घड़ियों को एकसाथ चलाए रखता है। चंद्रमा की घड़ी तिथि, पक्ष और महीना बताती है। सूर्य की घड़ी मौसम, साल और संक्रांति का संकेत देती है। दोनों में स्वाभाविक अंतर है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। अधिक मास इस अंतर को खत्म नहीं करता, बल्कि समय-समय पर संतुलित करता है। यह भारतीय कालगणना की व्यावहारिक और वैज्ञानिक व्यवस्था है।

अधिक मास न जोड़ा जाए तो जुलाई-अगस्त में मनेगी दीपावली

अधिक मास ऐसी व्यवस्था है जो चंद्रमा पर आधारित महीनों को सूर्य वाले महीनों के साथ मिलाए रखती है। अगर ये एक्स्ट्रा महीना कभी न जोड़ा जाए, तो चंद्रमा से बनी तिथियां हर साल सौर कैलेंडर के हिसाब से करीब 11 दिन पहले आने लगेंगी। इसका असर यह होगा कि हमारे त्योहार 3 साल बाद करीब 1 महीना पहले और 9 साल बाद पूरे 3 महीने पहले आने लगेंगे।

ऐसी स्थिति में, अक्टूबर-नवंबर में आने वाली दीपावली खिसककर जुलाई-अगस्त में आ जाएगी। मतलब, जो त्योहार अभी सर्दी या शरद ऋतु में आते हैं, वो धीरे-धीरे बरसात या गर्मी जैसे दूसरे मौसमों में पहुंच सकते हैं। अधिक मास इसी गड़बड़ी को रोकता है और इसी की वजह से हमारे त्योहार हमेशा अपने सही मौसम से जुड़े रहते हैं। जैसे- होली हमेशा वसंत में, दीपावली शरद ऋतु में और चातुर्मास वर्षा ऋतु में ही आते हैं।

एक्स्ट्रा महीना जोड़ने की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है

दुनिया के कई कैलेंडरों में चांद और सूरज की चाल को आपस में मिलाने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ने की वैज्ञानिक व्यवस्था अपनाई जाती है। यह व्यवस्था केवल हिंदू पंचांग तक सीमित नहीं है, बल्कि चीनी कैलेंडर सहित अन्य जगहों पर भी इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। ताकि उनके त्योहार और मौसम हमेशा सही तालमेल में रहें। चूंकि चंद्रमा का साल सूरज के साल से करीब 11 दिन छोटा होता है, इसलिए समय के इस बड़े अंतर को भरने के लिए बीच-बीच में एक पूरा एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है।

खगोल विज्ञान और पंचांग
सूर्य-चंद्रमा की चाल से बना अधिक मास का फॉर्मूला

जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उसके साथ चलता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 29.5 दिन (29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट) लगते हैं, और इसी समय को हम एक हिंदी महीना कहते हैं।

इस तरह जब चंद्रमा 12 चक्कर पूरे कर लेता है, तो हिंदी कैलेंडर का एक साल बनता है, जिसमें कुल 354 दिन होते हैं। दूसरी तरफ, पृथ्वी सूरज का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर का एक साल माना जाता है।

अब गणित ये है कि चंद्रमा और सूरज की इस चाल में हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है। तो 32 महीने, 16 दिन और 96 मिनट बाद यह अंतर बढ़कर एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। बस, इसी अंतर को बराबर करने के लिए हिंदी कैलेंडर में लगभग तीसरे साल एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं।

भोजशाला मंदिर में किस देवी को पूजा जाता है?

क्या है वाग्देवी का अर्थ और महत्व

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मंदिर को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, हाल के दिनों में यह प्राचीन स्थल विवादों के कारण चर्चा में आ गया है।लंबे समय से चल रहे भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे वाग्देवी मंदिर माना है।भोजशाला में ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां वाग्देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है।हिंदू समुदाय इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से इसे कमाल मौलाना मस्जिद होने का दावा करता रहा है।मान्यता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने कराया था।

कौन हैं मां वाग्देवी ?

वाग्देवी को देवी सरस्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है।उन्हें ज्ञान, वाणी, संगीत, कला और अभिव्यक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां वाग्देवी मनुष्य के भीतर ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश जगाने वाली देवी हैं।शास्त्रों में उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य बताया गया

है।वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और कमल पर विराजमान दिखाई जाती हैं।उनका यह रूप पवित्रता, ज्ञान और सृजन का प्रतीक माना जाता है.

क्या है 'वाग्देवी' शब्द का अर्थ ?

'वाग्देवी' दो शब्दों से मिलकर बना है - 'वाक' और 'देवी'.
'वाक' का अर्थ है वाणी या शब्द

'देवी' का अर्थ है दिव्य शक्ति

इस तरह वाग्देवी का अर्थ होता है "वाणी की देवी" या "शब्दों की देवी"।धार्मिक ग्रंथों में मां सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि के साथ-साथ वाणी एवं अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी देवी माना गया है।

मलमास में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए ?

मलमास को अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।17 मई 2026 यानी कल से मलमास शुरू हो चुका है, जो 15 जून 2026 तक रहेगा।मलमास के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं।इस दौरान मुंडन, गृह प्रवेश, शादी-ब्याह आदि शुभ कार्यों को करने पर रोक होती है।

धार्मिक महत्व के अनुसार, अधिक ज्येष्ठ मास होने के कारण इस वर्ष 12 महीने की बजाय 13 महीने होंगे.

हिंदू पंचांग के अनुसार, मलमास यानी अधिक मास।यह प्रत्येक 32-33 महीने में आने वाला एक अतिरिक्त 13वां महीना है।इसे सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच बैलेंस बनाने के लिए जोड़ा जाता है।दरअसल, चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है और सौर वर्ष 365 दिनों का।इस तरह से हर साल 11 दिनों का अंतर आ जाता है।यही फर्क तीन साल में एक महीने के बराबर होता है, इसलिए इसे अधिक मास कहा जाता है।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, विष्णु भगवान ने इस महीने को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है।मलमास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि आती है।परेशानियां दूर होती हैं।सासांरिक कार्यों को करने की बजाय इस समय को आध्यात्मिक साधना, आत्म-शुद्धि करने में लगाना चाहिए।साथ ही दान, पुण्य, जप, ध्यान, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, कथा आदि में मन लगाना चाहिए.

मलमास में क्या नहीं खाना चाहिए?

मलमास में मुख्य रूप से सात्त्विक जीवन, संयम और पूजा-पाठ पर अधिक ध्यान देना चाहिए।खानपान में निम्न चीजों के सेवन से परहेज करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

मांसाहार जैसे मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन वर्जित माना गया है.

-शराब और नशीली चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए वरना अशुभ होगा.

-लहसुन-प्याज (कई लोग पूरे महीने छोड़ देते हैं) खाने की मनाही होती है.

-बहुत ज्यादा तामसिक और मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए.

-बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि घर का बना ताजा खाना खाएं.

-कुछ लोग बाहर का जंक फूड और तला-भुना भी नहीं खाते हैं.

-काफी विष्णु भक्त एक समय ही भोजन करते हैं।फलाहार या व्रत रखते हैं.

-कुछ परंपराओं के अनुसार, दालें,अनाज छोड़ने का नियम भी है, लेकिन यह लोगों के अपने परिवार की परंपरा, क्षेत्र पर भी निर्भर करता है.

मलमास में क्या खाना चाहिए?

आप अधिक मास यानी मलमास में शुद्ध और सात्विक भोजन करें।मौसमी फल, दूध, दही, लौकी, धनिया, मिर्च, सेंधा नमक, जीरा, गेहूं, जौ, चना, मूंग, तिल, मूंगफली का सेवन कर सकते हैं।इस दौरान पालक, बैंगन, भिंडी खाना वर्जित माना गया है.

मलमास में क्या करना वर्जित माना जाता है?

परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, मलमास में निम्न मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं:

शादी-ब्याह, सगाई
मुंडन, जनेऊ जैसे संस्कार
बड़ी खरीदारी या शुभ कार्य
गृह प्रवेश
नया व्यापार/दुकान शुभ मुहूर्त में शुरू करना।

दिल्ली का 108 फीट श्री संकट मोचन धाम

आरती के समय खुलता है बजरंगबली का सीना

दिल्ली के प्रसिद्ध श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद हनुमान जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण साल 1994 में शुरू हुआ था।इसे पूरा होने में 13 साल लगे।करीब 2007 के आसपास यह मूर्ति पूरी तरह तैयार हुई।108 फीट ऊंची यह प्रतिमा दिल्ली की सबसे पहचान वाली धार्मिक जगहों में गिनी जाती है।इसके अलावा मंदिर में वैष्णो माता की गुफा भी बनाई गई है जो की भक्तों के लिए खास तौर पर आकर्षण का केंद्र है। मंदिर में अखंड ज्योति भी काफी समय से जल रही है।

मंदिर का पूरा नाम श्री सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फीट श्री संकट मोचन धाम है।कहा जाता है कि पहले यहां हनुमान जी का छोटा मंदिर हुआ करता था।समय के साथ यहां पूजा-पाठ बढ़ा और बाद में इसे भव्य रूप दिया गया।मान्यता है कि संतों की प्रेरणा और भक्तों के सहयोग से यहां विशाल मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ।धीरे-धीरे यह जगह दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शामिल हो गई।दिल्ली के करोलबाग और झंडेवालान के पास स्थित 108 फीट हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है।दूर से दिखने वाली बजरंगबली की विशाल मूर्ति इस मंदिर को खास बनाती है।दिल्ली मेट्रो से गुजरते वक्त भी यह मंदिर साफ दिखाई देता है, इसलिए यहां हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं।

इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है 108 फीट ऊंची बजरंगबली की मूर्ति।लेकिन यहां सिर्फ मूर्ति ही खास नहीं है क्योंकि यहां मंगलवार और शनिवार को खास आरती के समय हनुमान जी की प्रतिमा का सीना खुलता है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के दर्शन होते हैं।इसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं. इसके अलावा मंदिर का प्रवेश द्वार भी बेहद अलग है। यहां अंदर जाने का रास्ता एक बड़े मुख जैसा बनाया गया है।

मंदिर में रोजाना होने वाली आरती भी कम खास नहीं है। सुबह की आरती 6:00 से 6:30 AM के बीच होती है।शाम की आरती 7:30 से 8:00 PM के बीच होती है.इसके अलावा मंदिर में बड़े मंगलवार को विशेष भंडारा भी होता है और यहां पर मंगलवार शनिवार को हनुमान भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिलती है।

महाभारत : गांधारी ने दो बार ही आंखों से हटाई थी पट्टी, तब क्या हैरान करने वाली बात हुई

कौरवों की मां गांधारी आंखों से देख सकती थीं।जब उनके शादी अंधे धृतराष्ट्र से हुई तो उन्हें पहले तो जबरदस्त झटका लगा लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि पति की तरह अब वो भी किसी भी चीज को अपनी आंखों से नहीं देखेंगी, लिहाजा उन्होंने अपनी आंखों पूरे जीवन के लिए पट्टी बांध ली।लेकिन ये पट्टी दो मौकों पर जब उन्होंने खोली तो क्या गजब हो गया।

गांधार की राजकुमारी गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई थी।वह जन्म से ही अंधे थे।उन्होंने फैसला लिया कि वह उस दुनिया को नहीं देखेंगी, जिसे उनके पति नहीं देख सकते।उन्होंने इसी प्रण की वजह से अपनी पैदा हुई संतानों को भी कभी नहीं देखा।

गांधारी के बारे में कहा जाता था कि वह अंतर्ज्ञान से जानती थीं कि उनके आसपास और लोगों के मन में क्या चल रहा है।भीष्म ने गांधारी के गुणों और कुरु वंश के गौरव को देखते हुए इस विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे गांधारी के पिता सुबल ने स्वीकार कर लिया।आंख पर पट्टी बांधकर गांधारी अपने पति के साथ समान धरातल पर रहना चाहती थीं।हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधारी

ने ऐसा करके एक नेत्रहीन व्यक्ति से विवाह करने के लिए बाध्य किए जाने पर इस तरह अपना मौन विरोध जाहिर किया.

तब हर कोई अवाक रह गया

हालांकि गांधारी का अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला उनके चरित्र की दृढ़ता, त्याग और पतिव्रता धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को भी दिखाता है।गांधारी आंखों पर जो पट्टी पहनी हुई थी, उसका जिक्र महाभारत में भी आया है।कम से कम दो बार उनके पट्टी उतारने का जिक्र तो आया है। वो दोनों बहुत खास क्षण थे।और जब उन्होंने आंख से पट्टी हटाई तो वो मौके ऐसे थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया था।

तब गांधारी बहुत गुस्से में थीं

महाभारत के स्त्री पर्व में प्रसंग है जहां युद्ध के बाद गांधारी अपने मृत पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन को देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है।कुछ व्याख्याओं में कहा जाता है कि उन्होंने तब अपनी आंखों से पट्टी हटाई।उन्होंने युद्ध के मैदान में पड़ी लाशों के बीच अपने पुत्रों को मृत देखा।इस समय वह अंदर से इतने गुस्से में थीं कि उनके सामने जो आ जाता, वो गुस्से से भस्म ही हो जाता।लिहाजा उस समय कृष्ण ने पांडवों को उनके सामने नहीं आने के लिए कहा।

कृष्ण ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया

जब उन्होंने पट्टी बांध ली तब कृष्ण के साथ पांडव उनसे और धृतराष्ट्र से मिलने आए।आंख पर पट्टी बांधने के लिए बावजूद गांधारी अंदर से धधक रही थीं।वह तपस्वी थीं। गांधारी की तपस्या में संयम, धैर्य और त्याग का भी समावेश था।

हालांकि उस दिन अपनी तपस्या से प्राप्त दैवीय दृष्टि का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को शाप देने की कोशिश की। कहा जाता है कृष्ण ने गांधारी की उस शक्ति को नियंत्रित किया।

पैर का अंगूठा काला पड़ गया

तब गांधारी को अपनी पट्टी के निचले पोर से केवल युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा नजर आया और वह गांधारी के ताप के कारण काला पड़ गया। तब कृष्ण के कारण ही उनका गुस्सा कृष्ण पर उतरा और पांडव बच गए।

कब पहली बार गांधारी ने पट्टी हटाई

महाभारत में कहा गया है कि गांधारी ने पहली बार आंख से पट्टी महाभारत युद्ध से पहले हटाई थी।तब उन्होंने पुत्र दुर्योधन को अपने सामने वस्त्रविहीन यानि नग्न आने के लिए कहा था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

शांतिपूर्ण विरोध सबका अधिकार: सीजेआई

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर आम लोगों को परेशान करने, सड़कें जाम करने या भय का माहौल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। मामला उस मांग से संबंधित था, जिसमें एयरपोर्ट का नाम 'लोकनेता डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट' रखने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे। बेंच 'प्रकाशज्योत सामाजिक संस्था' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एयरपोर्ट के नाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

आतंकी गतिविधियां खत्म, भर्ती न के बराबर: एलजी सिन्हा

श्रीनगर,। जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के दावे के साथ नशे की चुनौती को बड़ा संकट बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नशे का आपस में संबंध है। नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हमारा ध्यान जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य में व्यापक सुधार आया है। आतंकी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई हैं और आतंकी भर्ती भी न के बराबर है। सुरक्षाबलों ने घाटी में सक्रिय सभी आतंकी संगठनों के शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बीएसएफ और सेना के जवान इन्हें विफल कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मारा गया है।

पूर्व सीएम खंडूरी का लंबी बीमारी के बाद निधन

देहरादून। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली, जिससे राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। अनुशासित नेतृत्व शैली और बेदाग सार्वजनिक छवि वाले खंडूरी उत्तराखंड के सबसे सम्मानित राजनीतिक व्यक्तियों में से एक थे। विभिन्न दलों के नेताओं ने अनुभवी राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शासन और जनसेवा में उनके योगदान को याद किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनीति में आने से पहले, खंडूरी ने भारतीय सेना में सेवा की और मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। लंबे सैन्य करियर के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधारों और जवाबदेही पर जोर देते हुए उत्तराखंड की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बी सी खंडूरी पहली बार 2007 में उत्तराखंड के सीएम बने और मार्च 2007 से जून 2009 तक इस पद पर रहे।

पूर्व जज वर्मा के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमी मुश्किलें

नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की मुश्किलें इस्तीफे के बाद भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश अधिनियम, 1968 के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए यह रिपोर्ट सोमवार को सौंपी गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित नोटिस दिए थे, जिन्हें स्वीकार कर जांच प्रक्रिया शुरू की गई थी। मामले की जांच के लिए गठित समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल थे। समिति का पुनर्गठन 25 फरवरी को किया गया था।

सीएम की पत्नी पर टिप्पणी: खेड़ा के बाद अब सुरजेवाला पर शिकंजा

डिसपुर। असम के सीएम हिमंता विश्वा सरमा की पत्नी पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा राजनीतिक विवाद थम नहीं रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद अब असम पुलिस ने कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर शिकंजा कसा है। मामले की जांच कर रही असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को समन जारी किया है।सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को 23 मई को गुवाहाटी में जांच अधिकारियों के सामने हाजिर होने का निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस माह पवन खेड़ा से हुई कई घंटों की पूछताछ में जो बातें सामने आईं, उसके आधार पर सुरजेवाला को यह समन भेजा गया है। इस घटनाक्रम से असम में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनातनी और तेज हो गई है। बता दें यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के सीएम हिमंता विश्वा सरमा की पत्नी को लेकर कथित तौर पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इन बयानों के बाद असम में एक शिकायत दर्ज कराई गई।

टीएमसी में हार का इतना खौफ, बीच चुनाव उम्मीदवारी वापस लेकर भागने लगे

जहांगीर खान ने फाल्टा विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस लिया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में होने वाले पुन: मतदान से पहले, टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मंगलवार को फाल्टा विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान का आदेश दिया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 29 अप्रैल को फाल्टा में हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है।

आयोग ने कहा कि सहायक मतदान केंद्रों सहित सभी मतदान केंद्रों पर 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुनर्मतदान होगा। मतों की गिनती 24 मई को होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार (18 मई) को निर्देश दिया कि फाल्टा विधानसभा पुनर्चुनाव में चुनाव लड़ रहे तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान के खिलाफ लंबित एफआईआर में 26 मई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अदालत ने राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को प्रथम दृष्टया ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को नए सिरे से चुनाव होने हैं और मतगणना 24 मई को होगी। व्यापक धांधली के आरोपों के बाद 29 अप्रैल को चुनाव रद्द कर दिए गए थे। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा

पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई, जिसमें सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

अदालत फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जहांगीर खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को सार्वजनिक करने और 21 मई को होने वाले पुनर्निर्वाचन से पहले किसी भी प्रकार की दमनकारी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जब पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने सुबह इस मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा था कि पुनर्निर्वाचन लड़ रहे खान को चुनाव अवधि के दौरान कई आपराधिक मामलों में निशाना बनाया जा रहा है।

ममता बनर्जी ने बुलाई नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों की बैठक

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपने 80 नवनिर्वाचित विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद अब टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। इस बैठक में पार्टी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की नई राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष की रणनीति तैयार करना है।

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, बैठक में एक बड़ा मुद्दा नगर निकायों के कामकाज को लेकर होगा। राज्य के कई नगर निकायों पर अभी भी टीएमसी का कब्जा है, लेकिन बदली हुई सत्ता के कारण वहां के अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव आया है। पार्टी इस प्रशासनिक असहयोग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करेगी।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कथित अवैध निर्माण के मामले में दिए गए हैं। केएमसी अधिनियम की धारा 400(1) के तहत जारी इन नोटिसों में संपत्ति मालिकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इन संपत्तियों की दीवारों पर नोटिस की प्रतियां भी चिपका दी गई हैं।

वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछले हफ्ते ही इन संपत्तियों की जांच के संकेत दिए थे। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें मिस्टर नेफ्यू (श्रीमान भतीजे) कहा था। अधिकारी ने दावा किया था कि उनके पास एक कंपनी से जुड़ी 24 संपत्तियों की सूची है।

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले-

देश में आने वाला है आर्थिक तूफान

रायबरेली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि भारत अभूतपूर्व आर्थिक तूफान के कगार पर है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वित्तीय संशोधनों का अंतत: पतन होगा और इसका सबसे अधिक बोझ आम नागरिक पर पड़ेगा। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक ढांचे को चुनिंदा अरबपतियों को श्रमिक वर्ग की कीमत पर लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया गया है।

गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां बड़े-बड़े कॉरपोरेट जगत के दिग्गज और राजनीतिक नेता अपने महलों में पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं, वहीं इस आसन्न संकट का असली असर उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे आंतरिक ढांचागत संकटों को दूर करने के बजाय लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं और साथ ही नागरिकों से विदेश यात्राएं कम करने का आग्रह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी ने आर्थिक ढांचे में बदलाव किया है और अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है। अंबानी के पक्ष में उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है, वह टिकेगा नहीं; उसका पूरी तरह से ढह जाना तय है। दुख की बात यह है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला आर्थिक संकट अडानी, अंबानी और मोदी को प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को प्रभावित करेगा। यह संकट शायद कई वर्षों में न देखी गई तीव्रता

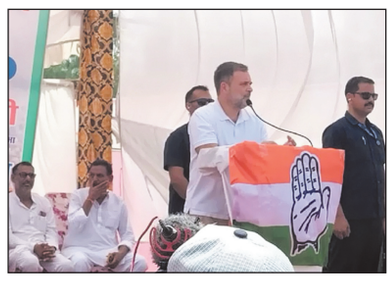

के साथ आने वाला है; आगे एक बहुत कठिन दौर है। ठोस कदम उठाने के बजाय, नरेंद्र मोदी देश को विदेश यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं, जबकि वे स्वयं विश्व भ्रमण पर निकले हैं।

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का केंद्र पर हमला

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नवीनतम वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतिगत विफलताओं को छिपाने की कोशिश करते हुए आम नागरिकों पर बोझ डाल रही है। उनकी यह टिप्पणी राज्य-संचालित तेल विपणन कंपनियों द्वारा एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद आई है। यह वृद्धि वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच हुई है।

खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछली मूल्य वृद्धि को मुश्किल से चार दिन हुए हैं, और मोदी सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं का बोझ जनता पर डालने की प्रक्रिया में पूरी तरह से जुटी है। कांग्रेस नेता ने भारत के तेल आयात और विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी को रूसी तेल खरीदने की अनुमति के लिए अमेरिका से एक महीने का विस्तार मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा है।

खरगे ने कहा कि ऐसा बार-बार करके वे 1.4 अरब भारतीयों के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, और किसी भी पिछली सरकार ने ऐसे उपाय नहीं किए थे। उन्होंने ईंधन मूल्य वृद्धि के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि यदि सरकार को ऐसा करने की अनुमति मिली है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बोझ अभी भी आम लोगों पर क्यों डाला जा रहा है। खरगे ने भाजपा सरकार पर आर्थिक स्थिति को संभालने में दूरदर्शिता और नेतृत्व की कमी का भी आरोप लगाया।

मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी टिप्पणी में सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले बड़े-बड़े बयान दिए और मितव्ययिता का उपदेश दिया। लेकिन अब अपनी विफलताओं का बोझ जनता पर डाल रही है। खरगे ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम नागरिकों को परेशान कर रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'मोदी, जो खुद को विश्व गुरु होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें रूसी तेल खरीदने की अनुमति के लिए अमेरिका से एक महीने का विस्तार मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा है।' खरगे ने आरोप लगाया कि यह कदम 1.4 अरब भारतीयों के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि केवल विदेश में प्रायोजित प्रचार अभियान चलाने से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। खरगे ने मोदी से जनता के प्रति जवाबदेही दिखाने का आग्रह किया।खरगे ने भाजपा सरकार पर दूरदर्शिता और नेतृत्व की गंभीर कमी का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि जब संकट आया, तो सरकार चुनावों में व्यस्त रही और मीठी-मीठी बातें करते हुए जनता को लूटने की योजना बनाती रही।

खेल
प्रमुख समाचार

केकेआर के लिए मुंबई के साथ करो या मरो का मुकाबला

कोलकाता। टूर्नामेंट की खराब शुरुआत के कारण अगर मगर की कठिन डगर में फंसी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम को अगर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखना है तो उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुधवार को यहां होने वाले मैच में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़नी होगी। मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है लेकिन वह केकेआर के समीकरण बिगाड़ने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

अगर इस मैच में केकेआर हार जाती है, तो अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में लगातार दूसरे सत्र में उसकी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रहेगी। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में खिताब जीतने के एक साल बाद 2025 में केकेआर आठवें स्थान पर रहा था। मुंबई के खिलाफ जीत से भी केकेआर का काम पूरा नहीं होगा। उसका भाग्य अभी भी शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मैच पर निर्भर करेगा। अगर पंजाब वह मैच जीत जाता है, तो रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर का आखिरी लीग मैच महज औपचारिकता रह जाएगा।

मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके हैं। इससे पांच टीम पंजाब किंग्स (13 अंक), राजस्थान रॉयल्स (12), चेन्नई सुपर किंग्स (12), दिल्ली कैपिटल्स (12) और कोलकाता नाइट राइडर्स (11) बाकी बचे एक प्लेऑफ स्थान हासिल करने की दौड़ में हैं। इनमें से केवल राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के ही दो मैच बचे हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 114 अंक फिसला निफ्टी 23618 पर बंद

मुंबई। मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवा दी और अंत में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिससे पूरे बाजार की रफ्तार धीमी पड़ गई।बीएसई सेंसेक्स 114.19 अंक यानी 0.15 प्रतिशत गिरकर 75,200.85 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 भी 31.95 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,618 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में दोनों प्रमुख इंडेक्स ने कई बार उतार-चढ़ाव देखा, लेकिन अंत में बढ़त कायम नहीं रख सके। विदेशी बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये पर दबाव बना रहा। कारोबार के दौरान रुपया 25 पैसे कमजोर होकर 96.61 के नए निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, दिन के अंत में यह थोड़ा संभला और 95.53 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 90 पैसे/लीटर का इजाफा

नईदिल्ली। देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। मंगलवार (19 मई) को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा किया। पिछले एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार है जब ईंधन महंगा हुआ है। इससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की संभावना है। इससे पहले, बीते शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब परिवहन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक दिखाई देने लगा है। फरवरी में शुरू हुए ईरान युद्ध के चलते दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। इसको देखते हुए सरकारी खुदरा पेट्रोलियम कंपनियों ने अपने बढ़ते नुकसान का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालने का फैसला किया।

देश का खाद्य तेल आयात 2025-26 में तीन प्रतिशत बढ़ा

नईदिल्ली। भारत का खाद्य तेल आयात वित्त वर्ष 2025-26 में तीन प्रतिशत बढ़कर 166.51 लाख टन हो गया। नेपाल से शुल्क-मुक्त आयात में तेज वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। उद्योग निकाय एसईए ने यह जानकारी दी। देश का खाद्य तेल आयात वित्त वर्ष 2024-25 में 161.82 लाख टन रहा था। उद्योग निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एसएएफटीए) समझौते के तहत भारतीय बाजारों में शून्य-शुल्क पहुंच का लाभ उठाने वाले नेपाल ने इस दौरान भारत को 7.36 लाख टन खाद्य तेल निर्यात किया, जो 2024-25 वर्ष के 3.45 लाख टन की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है। नेपाल से भारत को निर्यात में परिष्कृत सोयाबीन तेल का सबसे बड़ा हिस्सा रहा जबकि सूरजमुखी तेल, आरबीडी पामोलीन और सरसों तेल कम मात्रा में भेजा गया।

ईंधन महंगा होते ही कंपनियों ने बढ़ाने शुरू किए दाम

नईदिल्ली। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 3.90 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। ऐसे में बाजार को डर है कि अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहीं, तो कंपनियां अपने बढ़े हुए खर्च का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर देंगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी, लोगों का खर्च कम होगा और कंजम्शन सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। महंगाई का असर अब लोगों की रोज की जिंदगी में भी दिखने लगा है। देश की बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। मॉडर्न ब्रेड ने अपने बेसिक पैक की कीमत 5 रुपये बढ़ाई है। वहीं खबरें हैं कि ब्रिटानिया और Wibs जैसी कंपनियां भी जल्द अपने प्रोडक्ट्स महंगे कर सकती हैं।

संकट है पर इतना गहरा नहीं कि उसकी थाह न पा सकें

पूरन चंद सरीन

यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत के धार्मिक स्थलों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों, ट्रस्ट और कालेधन से खरीदे गए सोने का भंडार 15 से 20 हजार टन या इससे अधिक का होगा। इसका अर्थ है कि इसे अगर संवैधानिक और कानूनी तरीके से तिजोरियों से बाहर निकलवा लिया जाए और उसका इस्तेमाल तेल, गैस और अन्य नितांत आवश्यक वस्तुओं के आयात पर किया जाए तो हम वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट, अगर वास्तव में है, से बखूबी निपट सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह संभव कैसे हो? सीधा सा उत्तर है कि जैसे नोटबंदी की थी, वैसे ही सोनाबंदी कर दो, आधे-अधूरे मन से नहीं, जैसी 2014 में की थी।

किसी को परेशानी न हो और जो सोना खजाने में आए, उसके बदले में गोल्ड बांड दे दो, जिस पर इतना ब्याज या मुनाफा मिले कि बांड रखने वाले को एक अवधि के बाद भुनाने पर अफसोस न हो। आप सोना खरीदने पर सख्ती करेंगे और उसे सामाजिक व्यवस्था से बाहर धकेलेंगे तो सोने की तस्करी अंदर आ जाएगी। साल भर ही सही, सोना न खरीदने की बात कहते ही स्मगलर अपनी पौ बारह होने के सपने देखने लगे हैं क्योंकि इसकी खपत रोक पाना न तो उचित है और न ही संभव, बल्कि अर्थव्यवस्था के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है।

सोना कहां लगता है = यह समझना और सरकार द्वारा समझाया जाना जरूरी है कि सोना माइक्रोचिप्स, उच्च गुणवत्तापूर्ण इलैक्ट्रॉनिक कनैक्टर्स, रक्षा उपकरणों, उपग्रह तकनीक, दंत चिकित्सा और नैनो-रिसर्च तथा कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों में इस्तेमाल होता है। इसलिए सोना केवल निवेश या आभूषण नहीं, इसका वैज्ञानिक

और औद्योगिक उपयोग बड़े पैमाने पर होता है जैसे सैटेलाइट टैक्नोलॉजी, हाई प्रिसीजन सैंसर्स, मैडिकल डायग्नोस्टिक आदि। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता और अत्यधिक कंड्यूसिव होने से क्रिटिकल सिस्टम के लिए एकमात्र विश्वसनीय धातु है।

हमारे यहां सोना और चांदी कब और कौन खरीदता है? जाहिर है ब्याह-शादी के अवसर या तीज-त्यौहार जैसे दीवाली या गणेश चतुर्थी या किसी भी पर्व पर इसका खरीदना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद लॉकर में रख दिया जाता है और किसी विशेष अवसर पर ही बाहर निकलता है। वैसे भी गहने पहनकर निकलना खतरे से ख़ाली नहीं है। चेन खींचने की घटनाएं इसका उदाहरण है। वैसे हकीकत यह है कि रिजर्व बैंक में रखे सोने से कई गुना अधिक स्वर्ण भंडार इधर-उधर यहां-वहां तालों में बंद है लेकिन सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। धार्मिक या पारिवारिक सोना एक ऐसी वित्तीय शक्ति है जो यदि राष्ट्रीय संसाधन बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए, शर्त यही है कि जनता के साथ धोखा न हो और व्यवस्था कांच की तरह पारदर्शी तथा भागीदारी अपनी मर्जी से हो। देशवासियों द्वारा सोना न खरीदना समस्या का समाधान न होकर केवल थोड़े समय के लिए राहत मात्र है।

तेल-भारत की आर्थिक धड़कन = भारत की सबसे बड़ी आयात निर्भरता तेल है। तेल बचत का अर्थ आयात बिल कम होने से महंगाई का दबाव अधिक न होना है। आज वाहन केवल सुविधा नहीं, अर्थव्यवस्था का प्रतीक भी है। पैट्रोल और डीजल वाहन खरीदने में कई बार सस्ते लगते हैं लेकिन लंबी अवधि में ईंधन खर्च भारी पड़ सकता है। चलिए कोई नया वाहन खरीदना है तो बिजली से चलने वाला ले लेंगे लेकिन जिनके पास अभी पैट्रोल-डीजल से चलने वाली गाडियां हैं, वे उनका इस्तेमाल बंद या उन्हें कचरा तो होने देंगे नहीं, हां तेल महंगा हो जाएगा तो बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो निर्माता इन्हें बनाते हैं, वे फैक्ट्री में ताला तो लगाएंगे नहीं। अब समस्या यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात जब कही जाती है तो थोड़ी हंसी आती है क्योंकि सभी शहरों में मैट्रो नहीं चलती, बाकी सब जगह तो बस हो या रेल, इतनी असुविधा होती है कि यात्रा टालने में ही समझदारी लगती है।

दंतेवाड़ा प्रशासन की अनूठी पहल, उजर 100 योजना से संवरेगा मेधावियों का भविष्य

रायपुर। बस्तर अंचल के प्रतिभावान और जरूरतमंद युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने एक बेहद संवेदनशील और अनूठी शैक्षणिक पहल की है। जिले के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उजर 100 योजना शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन, चयन प्रक्रिया और पात्रता नियमों को तय करने के लिए आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्ययोजना का खाका तैयार किया गया।

स्थानीय को प्राथमिकता

योजना के तहत कुल 100 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसमें वर्गवार सीटें तय की गई हैं। जिसमे अनुसूचित जनजाति के 76,अनुसूचित जातिके 06,अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 और अनारक्षित के 04 सीटें शामिल है। इसके साथ ही कुल सीटों में 6 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहेगा। योजना का लाभ केवल दंतेवाड़ा जिले के मूल निवासी छात्रों को ही मिलेगा, जिन्होंने प्रथम प्रयास में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

'सुपर टैलेंटेड' बच्चों को पूरी छूट

सामान्यत: योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन ने प्रतिभा को नियमों में नहीं बांधा है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की प्रावीण्य सूची में जिले के शीर्ष 10 स्थान पाने वाले छात्रों और IIT, NIT, NEET, JEE, NDA AIIMS जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय परीक्षाओं में चयन पाने वाले विद्यार्थियों पर आय की कोई सीमा लागू नहीं होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉप 100 या सीबीएसई के टॉप 20 छात्र, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में चयनित विद्यार्थी, नक्सल प्रभावित परिवारों के बच्चे, खनन प्रभावित ग्रामों के छात्र और बीपीएल कार्डधारी परिवारों के होनहार बच्चे इस योजना में पहली प्राथमिकता पर होंगे।

सीधे खाते में आएगा पैसा

उजर 100 योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कॉलेज की फीस, हॉस्टल, भोजन और अध्ययन सामग्री का पूरा खर्च दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पूरी फीस सीधे संबंधित शिक्षण संस्थान को भेजी जाएगी। वहीं, हॉस्टल और किताबों का खर्च डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा

जिला प्रशासन ने मेधावियों के प्रोत्साहन के लिए बड़े कदम उठाए हैं। यदि जिले का कोई छात्र IIT, NIT, AIIMS, NEET या NDA जैसी परीक्षाओं में चुना जाता है, तो उसे संस्थान में रिपोर्टिंग या काउंसिलिंग के लिए जाने हेतु बस, रेल या हवाई यात्रा की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ड्रॉप लेकर तैयारी करने वाले छात्रों को विशेष परिस्थिति में कोचिंग सहायता भी मिलेगी।

ऑफलाइन होंगे आवेदन, बनेगी वेटिंग लिस्ट

चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में जमा किए जाएंगे। स्क्रूटनी, मेरिट लिस्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जिला स्तरीय कमेटी अंतिम मुहर लगाएगी।

ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोधः आज बंद रहेगी दवा दुकानें, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया समर्थन

रायपुर। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रदेशभर में 20 मई को दवा दुकानें बंद रहेगी। इस बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनियंत्रित कारोबार और इसके कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर मंडराते गंभीर खतरे के विरोध में 20 मई को प्रदेशव्यापी होलसेल और रिटेल दवा व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कृपलानी एवं कंफेडरेशन ऑफ फॉर्म डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वासुदेव जोतवानी ने संयुक्त रूप से चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी एवं चेम्बर पदाधिकारियों से मुलाकात कर बंद को लेकर समर्थन मांगा, जिस पर चेंबर ने अपना समर्थन दिया।

दवा बाजार के इस बड़े संकट और जनहित के इस संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने व्यापारियों की एकजुटता का परिचय देते हुए इस बंद को अपना पूर्ण और नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष राधा किशन सुंदरानी ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों द्वारा दवाओं पर अनियंत्रित और अत्यधिक छूट दी जा रही है, जो कि व्यापारिक नियमों के खिलाफ है।

कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी ने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बाजार में नकली दवाएं धड़ल्ले से खपायी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा प्रतिबंधित और अत्यधिक संवेदनशील दवाएं, जिन्हें सिर्फ डॉक्टर की लिखित सलाह (पर्चे) पर ही दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है, वे भी इन ऑनलाइन साइट्स पर बिना किसी कड़े सत्यापन के धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिसका चेम्बर विरोध करता है और इसे रोकने के लिए प्रशासन से निर्देश देने की अपील करता है।

कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों द्वारा अनियंत्रित छूट देना, नकली दवाओं के साथ प्रतिबंधित दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही है। यह स्थिति न केवल पारंपरिक दवा व्यापारियों के रोजगार को गर्त में धकेल रही है।

छत्तीसगढ़ में स्कूल शुल्क बढ़ा, नए शिक्षा सत्र से अभिभावकों पर बढ़ेगा आर्थिक भार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2026-27 से सरकारी हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्थानीय शुल्कों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की अनुशंसा पर शुल्क वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अगले शिक्षा सत्र से अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। जानकारी के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों में आयोजित होने वाली

विभिन्न गतिविधियों, परीक्षा सामग्री, खेल सामग्री और विज्ञान प्रयोगशाला से जुड़ी वस्तुओं की बढ़ती लागत को देखते हुए शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। प्रशासकीय समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन ने स्थानीय शुल्क में आंशिक वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

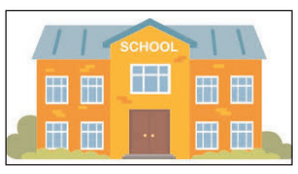

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, विद्यालयों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल गतिविधियों के संचालन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपयोग होने वाली सामग्री, खेल उपकरण और अन्य जरूरी शैक्षणिक संसाधनों की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुल्क संशोधन का निर्णय लिया गया है। हाईस्कूल स्तर पर कई मदों में शुल्क बढ़ाए गए हैं। कार्यकलाप शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया गया है। निर्धन छात्र सहायता निधि 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये की गई है। विज्ञान क्लब निधि 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी गई है। बलचर निधि 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये की गई है। वहीं क्रीड़ा निधि 50 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये कर दी गई है। विज्ञान प्रायोगिक शुल्क भी 50 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया गया है।

हालांकि रेडक्रॉस निधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और यह पहले की तरह 30 रुपये ही रहेगी। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी विभिन्न शुल्कों में वृद्धि की गई है। कार्यकलाप शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। निर्धन छात्र सहायता निधि 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये की गई है। विज्ञान क्लब निधि 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है। बलचर निधि 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये की गई है। क्रीड़ा निधि 65 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है।

सीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री चौधरी से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश की संभावनाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य उद्योग जगत और शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा विकास की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना रहा।

प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री को प्रदेश में उद्योगों के लिए उपलब्ध अवसरों, निवेशकों की अपेक्षाओं और औद्योगिक वातावरण को और अधिक मजबूत बनाने संबंधी सुझावों से अवगत कराया।

साथ ही राज्य में रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नई औद्योगिक नीतियों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया।वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

नागरिक सहकारी बैंकों में बढ़ेंगी आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं

रायपुर। राज्य के शहरी सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ महादेव कावरे ने समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में राज्य के 12 शहरी नागरिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सहकारिता आयुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नवाचारात्मक पहलों में सक्रिय

भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को बेहतर और आसान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एईपीएस (आधार आधारित भुगतान प्रणाली) जैसी सुविधाएं शुरू की जाएं। सहकारिता

आयुक्त ने बैंकों को यह भी निर्देशित किया कि वे तकनीकी सहायता और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए गठित अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें। इससे बैंकों को नई तकनीक अपनाने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेगी। बैठक में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के अधिकारी सुमीत हंस ने बैंकों को संगठन से जुड़ने के लाभ और उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे

सहकारी बैंक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को तेजी से लागू कर सकेंगे। इस अवसर पर व्यावसायिक सहकारी बैंक रायपुर, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर, लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक रायपुर, रायपुर अर्बन मर्केंटाइल को-ऑप बैंक, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, अंबिकापुर और जगदलपुर के सहकारी बैंक शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे ने सभी बैंकों को तय समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

पदाधिकारियों के साथ शाह के नाम ज्ञापन सौंपा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बस्तर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ता अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपने, उनसे मिलने जा रहे थे जिसे पुलिस ने रास्ते में रोक लिया तब कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन के प्रतिनिधियों को अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बस्तर के विकास के लिए तथा बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा तथा बस्तर की खनिज सम्पदा, जल, जंगल, जमीन की

संभावित बंदरबांट के संदर्भ में बस्तर की जनता की कुछ आशंकाएं हैं। हम सब बस्तर की जनता की तरफ से इसी संबंध में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तथा बस्तर के लोगों की आशंकाओं के लिए आपसे कुछ आश्वासन चाहते हैं। उम्मीद हैं आप बस्तर के नागरिकों के इन आशंकाओं का निराकरण करेंगे तथा बस्तर की जनता के में मन में उठ रहे सवालों का जवाब देंगे।

बस्तर के लोग जानना चाहते हैं तथा डबल इंजन की सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि-1. नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट आपके सरकार के विनिवेशीकरण के सूची में शामिल है। यह स्टील प्लांट नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी देंगे क्या? एनएमडीसी मुख्यालय जगदलपुर बस्तर कब लायेंगे।

अमित शाह नक्सलवाद पर राजनीति कर रहेः शुक्ला

रायपुर। नक्सलवाद के मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजनैतिक विद्वेष के कारण गलत बयानी किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को गलत बयानी शोभा नहीं देती। जब कांग्रेस की सरकार थी तब अपने हर दौरे में वे नक्सल नियंत्रण के मामले में भूपेश सरकार की तारीफ करते थे। आंकड़े बताते है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान नक्सली घटनाओं में

कमी आई थी। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्वंय अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आकर 5 अप्रैल 2021 को मीडिया में बयान दिया था कि राज्य की भूपेश सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर नक्सलवाद को पीछे खदेड़ दिया है। राज्य में नक्सली घटनाओं में 80 प्रतिशत तक की कमी आई है। अमित शाह के सामने आरपीएफ के डीजीपी ने कहा था छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी पैकअप की ओर है। आज गृह मंत्री की कांग्रेस सरकार के प्रयासों पर ऊँगली उठा रहे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विश्वास विकास सुरक्षा के मूल मंत्र से नक्सलवादी घटनाओं और नक्सलवाद पर कमी आई थी।

पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाकर जनता से लूट की छूटः ठाकुर

रायपुर। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई वृद्धि को पेट्रोलियम कंपनियों को जनता को लूटने की छूट करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार में कंपनी राज चल रहा है। जिस प्रकार पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रहे है। ऐसा लग रहा है सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को जनता को लूटने की खुली छूट दे दी है। सरकार

जब जनता के बजाय कंपनियों की नफा नुकसान की चिंता करे, तो जनता तो महंगाई की बोझ तले दबती जायेगी। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि करने पहले कृत्रिम संकट पैदा किया। ताकि पेट्रोल, डीजल के दाम मनमाफिक बढोत्तरी किया जा सके और जनता परेशान होकर इसे स्वीकार कर ले। खेद जनक है पेट्रोलियम कम्पनियों के कठपुतली बनकर सरकार भी सिर हिला रही है, सरकार को जनता की थोड़ी भी फिक्र नहीं है। जनता की मजबूरी है पेट्रोल, डीजल खरीदना और उसी मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी मुनाफाखोरी को बढ़ा सकें। जब क्रूड ऑयल के दाम 30 डॉलर से कम थे तब कम्पनियां रोज 100 करोड़ से अधिक मुनाफा कमाई आम जनता के जेब से 34 लाख करोड़ की कमाई की, तब सरकार को जनता के साथ हो रही लूट की चिंता नही थी।

भ्रष्टाचार का अवसर तलाशने के लिए ही खुले में छोड़ाः वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने भ्रष्टाचार के लिए अवसर तलाशने के लिए ही धान का निराकरण नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से प्रदेश के धान संग्रहण केंद्रों में 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान पड़ा हुआ है, जो खुले में है। सरकार अभी तक 15 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान मिलरों को नहीं दे पाई है। सरकार

इस धान का निराकरण क्यों नहीं कर रही है? भ्रष्टाचार करने की नीयत से भाजपा सरकार संग्रहण केंद्रों से मिलरों को मीलिंग के लिए धान नहीं दे रही, ताकि धान खराब होने के नाम पर एवं खुले बाजार में नीलामी करके भ्रष्टाचार किया जा सके। पूरे प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन उठाव के अभाव में संग्रहण केंद्रों में जमा पड़ा है। पूरे प्रदेश में 15 लाख टन से अधिक धान खुले में पड़ा है। भाजपा डबल इंजन की सरकार का दंभ भरती है तो केंद्र सरकार से बोलकर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये पूरे धान से बने चावल को सेंट्रल पुल में क्यों नहीं दे देती, जब इतना भी नहीं हो सकता तो डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा? यह धान जो खराब हो रहा जिसे 3100 रू. में खरीद कर 2000 में बेचना पड़ेगा, वह राज्य की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे का है, किसानों ने मेहनत से ऊपजाया है।

एडमिशन फेयर 2026 : रायपुर में 20 और 21 मई को

रायपुर। क्या आप भी अपने उच्च शिक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है. राजधानी रायपुर में अफेयर्स लेकर आ गया है एडमिशन फेयर 2026. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रमुख्य विश्वविधायालयों का मेला लगेगा, जहां एक ही छत के नीचे उच्च शिक्षा से जुड़े हर सवालों के जवाब और बेहतर करियर पाथ चुनने का मौका मिलेगा. एडमिशन फेयर 2026 खास तौर पर कक्षा 12वीं के छात्रों, माता-पिता और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आयोजित किया जा रहा है. यह कार्यक्रम 20 मई और 21 मई को 'बेबीलॉन कैपिटल' में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा। यह एडमिशन फेयर भारत के वर्तमान शिक्षा परिदृश्य को देखते हुए बेहद प्रासंगिक है. इस फेयर में देशभर के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संस्थानों के साथ-साथ एडमिशन डायरेक्टर से सीधे संवाद कर छात्र अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं. यहां कक्षा 12वीं या उससे आगे के पाठ्यक्रम विकल्प, फीस, प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, स्कॉलरशिप विकल्प समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां सटीक, विश्वसनीय और नवीनतम रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी. अफेयर्स एग्जीबिशन एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ विवेक शुक्ला ने कहा कि हम एक बार फिर रायपुर में 'एडमिशन फेयर' आयोजित करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

'बस्तर में सुशासन का सफर

अब गाँव की चौखट तक पहुँची बस सेवा

धनंजय राठौर, अशोक कुमार

रायपुर। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां के कई गांव दशकों से मुख्यधारा से कटे हुए थे। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने इस दूरी को पाटते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा के जरिए विकास का एक नया अध्याय शुरू किया है।

अब बस्तर के सुदूर वनांचलों में विकास की एक नई बयार बह रही है। वहीं दशकों के इंतजार के बाद, अब गांवों की पगडंडियों पर भी अब बस के पहिए थिरकने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार 'अंत्योदय' के संकल्प को चरितार्थ कर रही है।

'दशकों का सपना, अब हुआ साकार'

आजादी के बाद से जिन 425 गांवों के ग्रामीणों ने केवल पैदल चलने या निजी साधनों पर निर्भर रहने की नियति चुनी थी, आज वहां नियमित बसों की आवाज और उनके हॉर्न गूंज रही हैं। बस्तर संभाग

के 50 विभिन्न मार्गों पर मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की 52 बसों का सफल संचालन किया जा रहा है। यह मात्र एक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों की उम्मीदों की उड़ान है, जो अब अपने घर की दहलीज से सीधे शहर की ओर जुड़ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि परिवहन मंत्री केदार कश्यप के सक्रिय प्रयासों और परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश के मार्गदर्शन से इन मार्गों का चयन बहुत ही व्यावहारिक तरीके से किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीणों को हाट-बाजार, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों तक पहुँचने में कोई बाधा न आए। परिवहन विभाग अब केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि श्अंतिम छोर के व्यक्तिश् तक सेवा पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

'शिक्षा की नई रोशनी': सुदूर क्षेत्रों के छात्र अब उच्च शिक्षा के लिए शहरों के कॉलेजों तक आसानी से आ-जा पा रहे हैं। परिवहन की सुविधा ने युवाओं के सपनों को नई गति दी है।

'बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं': स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच अब सुलभ हो गई है। आपातकालीन स्थिति हो या नियमित जाँच, ग्रामीणों को अब निजी वाहनों के भारी खर्च और असुरक्षित सफर से मुक्ति मिली है।

'आर्थिक सशक्तिकरण': बस्तर की आर्थिक रीढ़ यहाँ की लघु वनोपज और कृषि उत्पाद हैं। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीण अपनी उपज को कम लागत में बड़े बाजारों तक पहुँचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

प्रदेश में तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य देश में सर्वाधिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा है। विभाग केवल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पत्तों की खरीदी करता है। कटे-फटे और निम्न गुणवत्ता के पत्ते रिजेक्ट किए जाते हैं। यह जानकारी प्रबंध संचालक

रिजेक्ट पत्तों का विक्रय वैध: प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर ने बताया कि रिजेक्ट तेंदूपत्तों पर संग्राहकों का स्वामित्व है। वे अपनी वनोपज को निजी स्तर पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह वैध व्यापारिक प्रक्रिया है, इसे श्तस्करीश् नहीं कहा जा सकता।

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य सुचारु रूप से संचालित: 18 मई

2026 तक सुकमा में 84 हज़ार 382 मानक बोरा यानी लक्ष्य का 77.84: संग्रहण हो चुका है। कोन्टा क्षेत्र की 5 समितियों में 100: से अधिक संग्रहण हुआ है। राज्य में कुल 11.64 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण हुआ है। 46 हज़ार 625 संग्राहक जुड़े हैं, जो पिछले वर्ष से अधिक है।

निगरानी जारी: ओडिशा सीमा से लगे क्षेत्रों में वन विभाग की सघन गश्त और रात्रिकालीन पेट्रोलिंग जारी है। अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है।

कोरिरास सहित किसी भी फड़ में तेंदूपत्ता सड़ने या दीमक लगने की स्थिति नहीं है। संग्रहण प्रक्रिया पारदर्शी है और भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.